वर्ष 13 • अंक 4 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 20 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 4

डिफॉल्ट रेटिंग पर समिति के सवाल

ईएस रंगनाथन ▸▸ पृष्ठ 2

आईजीएल को बेहतर मार्जिन की आस

डॉलर रु. 71.60 (बाजार बंद) | यूरो रु. 77.50 (बाजार बंद) | सोना (10ग्राम) रु 41469 ▲ 499 रुपये | सेंसेक्स 41323.00 ▲ 428.60 | निफ्टी 12125.90 ▲ 133.40 | निफ्टी फ्यूचर्स 12142.70 ▲ 16.80 | ब्रेंट क्रूड 58.10 डॉलर ▲ 0.80 डॉलर

एक नज़र

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब स्वैच्छिक हुई

सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में बड़े बदलावों को बुधवार को मंजूरी दे दी। योजना की खामियों को दुरुस्त करते हुए अब इसे किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है। फरवरी 2016 में शुरू की गई इस फसल बीमा योजना के तहत, ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह बीमा कवर लेना अनिवार्य रखा गया था। मंत्रिमंडल ने साथ ही डेयरी क्षेत्र को गति देने के लिए 4,458 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दे दी। इससे 95 लाख किसानों को लाभ होगा। पृष्ठ 4

सरकार नहीं स्वीकार कर रही आर्थिक सुस्ती की बात

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार आर्थिक मंदी की बात स्वीकार नहीं कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश में ऐसी सरकार है, जो देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। योजना आयोग (अब नीति आयोग) के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की किताब के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि अगर देश के समक्ष आईं चुनौतियों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो एक विश्वसनीय समाधान कभी नहीं मिलेगा। सिंह ने कहा कि 8 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल हो सकती है, लेकिन इसके लिए वित्तीय नीतियों में बदलाव और साहसिक कर सुधारों की जरूरत है। पृष्ठ 4

12 दवाएं, इन्ग्रेडिएंट्स का निर्यात रोकने की सिफारिश

चीन में कोरोनावायरस फैलने के कारण वहां से दवा बनाने के लिए आयातित कच्चे माल की आपूर्ति पर नजर रखने के लिए गठित एक सरकारी समिति ने 12 ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएंट्स (एपीआई) और दवाओं के निर्यात पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इन एपीआई और दवाओं में सामान्य एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स शामिल हैं। बुधवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को भेजे एक पत्र में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उप सचिव एम के भारद्वाज ने 12 एपीआई और दवाओं के निर्यात पर रोक लगाने को कहा है। पृष्ठ 12

देश भर में स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति 1 अप्रैल से

देश सबसे स्वच्छ पेट्रोल-डीजल अपनाने के लिए तैयार है और 1 अप्रैल से नए उत्सर्जन मानक भारत चरण-6 के अनुकूल ईंधन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने बुधवार को यह दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने वाहन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत चरण-4 से सीधे भारत चरण-6 मानक पर अमल करने का निर्णय लिया था और महज तीन साल में इसे सफलता से अमल में लाने के करीब है।

शेयर बाजारों में तेजी सेंसेक्स 428 अंक उछला

शेयर बाजारों में बुधवार को गिरावट थम गई। चीन में कोरोनावायरस के नए मामलों में कमी आने की खबरों और भारत पर इसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए जल्द कदम उठाने की केंद्र सरकार की घोषणा से निवेशकों की धारणा में सुधार दिखा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 428 अंक चढ़कर 41,323 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 133.40 अंक यानी 1.11 फीसदी की बढ़त के साथ 12,125.90 अंक पर बंद हुआ।

डिश टीवी-भारती में नहीं बनी बात

एस्सेल समूह और भारती एयरटेल के बीच सौदे पर हो रही थी बात

मूल्यांकन पर मतभेदों के कारण सौदे से किया किनारा

वित्तीय निवेशक से बातचीत कर रहे हैं प्रवर्तक

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 19 फरवरी

डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) कंपनी डिश टीवी को लेकर कंपनी प्रवर्तक एस्सेल समूह के सुभाष चंद्रा और भारती एयरटेल के सुनील भारती मित्तल के बीच प्रस्तावित सौदा मूल्यांकन पर मतभेदों के कारण रद्द हो गया है।

प्रवर्तक एस्सेल समूह की डिश टीवी में 62 फीसदी हिस्सेदारी है। समूह अब कंपनी में अपनी आधी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक वैश्विक वित्तीय निवेशक से बातचीत कर रहा है। एस्सेल समूह की योजना इस सौदे से मिलने वाली नकदी से अगले 12 महीने में अपनी प्रमुख कंपनी ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (जेडईईएल) में 5 फीसदी हिस्सेदारी की पुनर्खरीद करने की है।

सूत्रों के मुताबिक एस्सेल समूह को इस सौदे से करीब 2,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पहले प्रवर्तक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारती एयरटेल से बातचीत चल रही थी।

ज़ी के शेयरों की खरीद की पहली पेशकश मौजूदा वित्तीय निवेशकों को की जाएगी जिसमें ओपनहाइमर और जीआईसी शामिल हैं। ओपनहाइमर की डिश टीवी में करीब 19.86 फीसदी और जीआईसी की 10 फीसदी हिस्सेदारी है। इससे प्रवर्तकों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा जो अभी केवल 5 फीसदी है। प्रवर्तकों के करीबी सूत्रों के मुताबिक उनकी योजना कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 26 फीसदी करने की है। हालांकि एस्सेल समूह के एक प्रवक्ता ने इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

जेडईईएल के प्रवर्तकों की साथ ही 26 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेरिका के एक रणनीतिक निवेशक के साथ भी बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक संभावित निवेशक प्रवर्तकों को कंपनी का कामकाज चलाने की अनुमति देना चाहता है। कंपनी का परिचालन राजस्व 6166.1 करोड़ रुपये और बाजार पूंजीकरण 2046 करोड़ रुपये है। हालांकि उसके उपभोक्ताओं की संख्या 2.394 करोड़ है जो टाटा स्काई से थोड़ा ही कम है। लेकिन डिश टीवी भारती एयरटेल से बहुत आगे है जिसकी 6.9 करोड़ उपभोक्ताओं वाले डीटीएच बाजार में 23.39 फीसदी हिस्सेदारी है।

भारती एयरटेल अपने डीटीएच परिचालन का विस्तार करना चाहती है ताकि वह रिलायंस जियो की आक्रामक रणनीति को टक्कर दे सके। डिश टीवी के अधिग्रहण से वह डीटीएच बाजार में 54.62 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी के साथ टाटा स्काई से कहीं आगे पहुंच जाती। एयरटेल ने एक दोहरी रणनीति अपनाई है। डीटीएच सेवाओं के अलावा वह फाइबर टु होम के मामले में बीएसएनएल के बाद दूसरे सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के 22 लाख ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं जौकि रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं की संख्या करीब दस लाख है। हालांकि हैथवे और डेन कैबल के भी कुछ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं। इन दोनों कंपनियों का अधिग्रहण रिलायंस ने किया है।

एस्सेल समूह गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इसकी वजह यह है कि उसने जेडईईएल के शेयरों को गिरवी रखकर अपनी बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ऋण लिया था। अभी उसे 2500 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान करना है।

बाजार पर पकड़

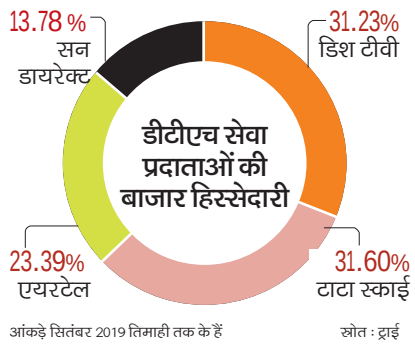

आंकड़े सितंबर 2019 तिमाही तक के हैं | स्रोत : ट्राई

डिश टीवी में किसका, कितना हिस्सा*

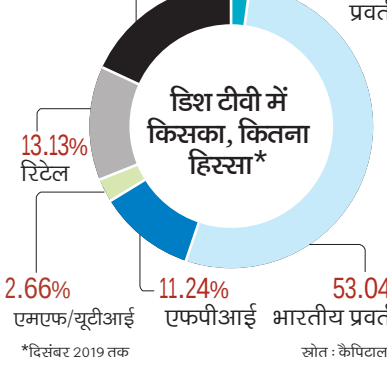

*दिसंबर 2019 तक | स्रोत : कैपिटालाइन

ट्रंप के दौरे पर नहीं होगा व्यापार सौदा

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 19 फरवरी

- ट्रंप ने किया संभावनाओं को खारिज
- भारत में ज्यादा टैरिफ से खुश नहीं हैं ट्रंप
- व्यापक सौदे में लगेगा लंबा समय
- कृषि पर हो सकता है सीमित करार

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उनके इस महीने होने वाले भारत दौरे में द्विपक्षीय व्यापार सौदे की उम्मीदों को खत्म करते हुए आज कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक सौदे को अंतिम रूप देने में अभी लंबा समय लगेगा। ट्रंप ने वॉशिंगटन में कहा, 'हमारा भारत के साथ व्यापार सौदा हो सकता है लेकिन मैं बड़े सौदे को बाद के लिए बचाकर रख रहा हूं। हम भारत के साथ बड़ा व्यापार समझौता कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि यह चुनाव से पहले हो पाएगा या नहीं।' अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इस साल नवंबर में होने हैं।

ट्रंप ने यह संकेत भी दिया कि वह भारत में अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क के मौजूदा स्तर से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद करता हूं।' ट्रंप कई बार भारत को 'टैरिफ किंग' कह चुके हैं।

उनका कहना है कि भारत में ज्यादा टैरिफ के कारण अमेरिका के उत्पाद वहां प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाते हैं। सूत्रों का कहना है कि बतौर राष्ट्रपति ट्रंप की पहली भारत यात्रा में सैन्य साजोसामान की बिक्री के बारे में दोनों देशों के बीच एक सौदा होने की उम्मीद है। इसमें नौसेना के लिए 24 हेलीकॉप्टरों और प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की बिक्री शामिल है। लेकिन राजनयिक सूत्रों का कहना है कि ट्रंप के दौरे में भी व्यापार सौदे के बारे में बातचीत जारी रहेगी।

वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'कृषि पर बातचीत जारी है और ट्रंप तथा मोदी की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में इसका जिक्र हो सकता है।' इसके तहत भारत अमेरिका से आयात होने वाले बादाम, अखरोट, सेब और शराब जैसे महंगे कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी की जा सकती है। पिछले साल अमेरिका से आयात होने वाले 29 उत्पादों पर 50 फीसदी तक सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था।

पिछले बजट में अमेरिका से आयात होने वाले चिकित्सा उपकरणों पर अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकर लगाने की घोषणा की थी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में गतिरोध जारी है। भारत के चिकित्सा उपकरणों के बाजार में अब भी अमेरिका का दबदबा है लेकिन चीन और जर्मनी से होने वाले सस्ते आयात के कारण उसकी हिस्सेदारी घट रही है। भारत ने साफ किया है कि वह इस कर को वापस नहीं लेगा लेकिन सूत्रों का कहना है कि कोरोनरी स्टेंट जैसे कुछ महंगे सामान पर ट्रेड मार्जिन पॉलिसी की अनुमति दी जा सकती है। एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के औद्योगिक कलपुर्जों, इंजीनियरिंग उत्पादों और स्मार्टवॉच तथा आईफोन जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी करने जैसे मुद्दों पर ट्रंप के दौरे के बाद ही इन पर चर्चा की जा सकती है।

भारत चाहता है कि अमेरिका जीएसपी योजना के तहत भारतीय सामान को मिलने वाली छूट को फिर से बहाल करे लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया है। व्यापार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने पिछले सप्ताह भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखकर अपनी मंशा साफ कर दी है लेकिन भारत इसका समर्थन नहीं करता है।

दूरसंचार क्षेत्र को उबारने पर ध्यान दे सरकार

भाषा
नई दिल्ली, 19 फरवरी

> "दूरसंचार क्षेत्र पिछले साढ़े तीन साल से दबाव में है, ऐसे में सरकार को इस क्षेत्र की सेहत पर ध्यान देना चाहिए।"
> **सुनील भारती मित्तल**
> **चेयरमैन, भारती एयरटेल**

देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल ने बुधवार को कहा कि दूरसंचार क्षेत्र पिछले साढ़े तीन साल से दबाव में है, ऐसे में सरकार को इस क्षेत्र की सेहत पर ध्यान देना चाहिए।

नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलने पर मित्तल ने संवाददाताओं से कहा उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उत्पन्न समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के भुगतान मुद्दे पर बैठक मे कोई चर्चा नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि दूरसंचार उद्योग सरकार के डिजिटल एजेंडा और देश के लिए व्यापक महत्त्व वाला है। ऐसे में सरकार को यह देखने की जरूरत है कि इस क्षेत्र को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है। मित्तल ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद जो भी भुगतान करना है उसके लिए एयरटेल ने पहले ही अपनी योजना की घोषणा कर दी है। कंपनी ने उसकी कुल 35,000 करोड़ रुपये की बकाया देनदारी में से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार को कर दिया है। वित्त मंत्रालय में जाने से पहले मित्तल ने दूरसंचार सचिव से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कंपनी कुल देनदारी की गणना कर रही है। इससे पहले वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने भी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। बहरहाल, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात एक साथ ही अथवा अलग अलग मिले। मंगलवार को भी बिड़ला ने दूरसंचार सचिव से मुलाकात की थी। वोडाफोन आइडिया ने अपने कुल एजीआर बकाये में से अभी केवल 2,500 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है।

इससे पहले दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों को अपना पूरा बकाया 17 मार्च का उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई तक चुकाने के लिए पत्र भेजा है। इस बीच दूरसंचार विभाग दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा बकाया भुगतान में विफल रहने पर उनकी बैंक गारंटी भुनाने की संभावना के बारे में सोलिसिटर जनरल से राय मांगी है।

वोडा-आइडिया के शेयरों में तेजी

सरकार द्वारा बैंक गारंटी नहीं भुनाए जाने की उम्मीद के बीच वोडाफोन आइडिया का शेयर बुधवार को 38 फीसदी चढ़ गया। बीएसई पर कंपनी का शेयर कारोबार के दौरान 48.18 फीसदी चढ़कर 4.49 रुपये पर पहुंच गया था। लेकिन कारोबार की समाप्ति पर यह 38.28 फीसदी बढ़त के साथ 4.19 रुपये पर बंद हुआ। पिछले सात दिनों से वोडाफोन आइडिया के शेयर में गिरावट बनी हुई थी।

10 गारंटी पूरा करने के लिए हरकत में आई केजरीवाल सरकार

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 19 फरवरी

- एक सप्ताह के अंदर कार्ययोजना के साथ हर गांरटी की समयसीमा व बजट बताना होगा
- दिल्ली मंत्रिमंडल की **24** फरवरी से तीन दिवसीय विधानसभा सत्र को मंजूरी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें अधिकारियों को 10 गारंटी पूरा करने के लिए एक सप्ताह में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दिल्ली मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी से शुरू होने वाली दिल्ली विधानसभा के तीन दिवसीय सत्र को मंजूरी दी। इस सत्र में विधायकों शपथ दिलाने के साथ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस बीच, केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा की।

केजरीवाल ने कहा कि अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर हर गारंटी के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्ययोजना में यह बताना होगा कि कौन सी गारंटी कितने महीने या साल में पूरी होगी और इसमें कितना पैसा खर्च होगा? उन्होंने बताया कि इस कार्ययोजना के अनुरूप गारंटी पूरा करने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत होगी, उसका आवंटन आगामी बजट में किया जाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली, घरों में पाइपलाइन से पीने लायक पानी, हर बच्चे को शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सुलभ परिवहन, कचरा व प्रदूषण मुक्त दिल्ली, महिला सुरक्षा, कच्ची कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं और झुग्गीवालों को पक्के मकान देने की गारंटी दी है।

इस बीच, दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने नई सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली के उद्यमियों से मुलाकात की। आप व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक बृजेश गोयल ने बताया कि उद्योग मंत्री ने कारोबारियों को इंसपेक्टर राज से निजात दिलाने समेत चुनावी वादे निभाने का भरोसा दिया। उद्यमियों ने मंत्री के सामने उद्योग फ्री होल्ड, सर्कल दरों को तर्कसंगत बनाने, औद्योगिक बिजली दरों में राहत देने आदि मुद्दों को उठाया।

चीन में संकट से सैमसंग को मिला दम

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 19 फरवरी

- भारतीय हैंडसेट बाजार में पकड़ मजबूत बनाने में जुटी सैमसंग
- चीन से आपूर्ति प्रभावित होने से चीनी फर्मों के परिचालन पर असर
- सैमसंग नए हैंडसेट बाजार में उतारने की कर रही तैयारी
- वियतनाम में बड़ा केंद्र होने से सैमसंग की आपूर्ति पर नहीं पड़ा ज्यादा असर

चीन में जनवरी की शुरुआत में फैले कोरोनावायरस ने जहां लाखों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया है, वहीं हजारों कारोबार पर भी इसका असर पड़ा है। लेकिन कुछ कंपनियों को इस स्थिति से फायदा होता भी दिख रहा है। भारत में अधिकांश अग्रणी मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की कारोबारी योजना पर असर पड़ा है लेकिन सैमसंग को बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिली है।

ऐपल, श्याओमी, ओप्पो, वीवो और रीयलमी जैसे मोबाइल विनिर्माताओं को अपने नए हैंडसेट लाने की तिथि और कीमत रणनीतियों में बदलाव करना पड़ रहा है, वहीं सैमसंग ने इस मामले में इन पर बढ़त बना ली है। भारतीय मानक ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार कोरियाई कंपनी सैमसंग की स्थानीय इकाई ने 2020 की शुरुआत में 9 नए हैंडसेट बाजार में उतारने की योजना बनाई है जबकि ऐपल, श्याओमी, वीवो, ओप्पो और रीयलमी की ओर से इस तरह की कोई योजना नहीं बताई गई थी। रेडमी (श्याओमी का ब्रांड) और एलजी ने भारतीय मानक ब्यूरो के पास 1 जनवरी से अब तक केवल दो-दो मॉडल पंजीकृत कराए हैं, वहीं मोटोरोला और कूलपैड ने एक-एक मॉडल पंजीकृत कराए हैं।

दिल्ली का स्थानीय ब्रांड सेलीकोर ने 1 जनवरी से 15 नए मॉडल पंजीकृत करा इस सूची में सबसे आगे है। इसी तरह भारतीय ब्रांड हाईटेक ने तीन मॉडल पंजीकृत कराए हैं।

टेकआर्क के लीड एनालिस्ट फैसल कवूसा के अनुसार प्रमुख मूल उपकरण विनिर्माता नए मॉडल लोने में देरी कर रहे हैं। आमतौर पर भारतीय मानक ब्यूरो के पास पंजीकृत कराने के 4 से 6 हफ्ते में संबंधित मॉडल बाजार में आ जाते हैं। लेकिन पंजीकरण की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले कुछ महीनों में कितने नए उत्पाद बाजार में आ सकते हैं। अभी तक की स्थिति से सैमसंग को लाभ मिलता दिख रहा है क्योंकि उसकी आपूर्ति श्रृंखला पर कम असर पड़ा है।

चीन में अधिकतर विनिर्माण गतिविधियां निलंबित हैं और अहम पुर्जे तथा हैंडसेट की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है, जिसका असर चीन की फर्मों पर पड़ता दिख रहा है। हालांकि उनमें से कई ने भारत में अपने संयंत्र लगाए हैं लेकिन वे भी चीन से होने वाली आपूर्ति पर बहुत हद तक निर्भर हैं।

सैमसंग अपने अधिकतर हैंडसेट का विनिर्माण स्थानीय स्तर पर करती है और 2018 में उसने अपने नोएडा संयंत्र की क्षमता में भी इजाफा किया था। उसकी स्थापित क्षमता अब दोगुनी होकर सालाना 12 करोड़ हैंडसेट विनिर्माण की हो गई है। इसके साथ ही उसके मुख्य पुर्जों की आपूर्ति इन-हाउस होती है और उसका सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र वियतनाम में है। इन सबका फायदा सैमसंग को मिल रहा है।

(शेष पृष्ठ 12 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

टॉरंट फार्मास्युटिकल्स

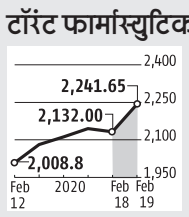

बायोकॉन, सिप्ला को पीछे छोड़कर बनी चौथी सबसे मूल्यवान औषधि कंपनी

₹ 2,132.00 पिछला बंद भाव
₹ 2,241.65 आज का बंद भाव
▲ 5.14 %

हिंदुस्तान यूनिलीवर

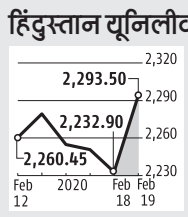

विश्लेषकों ने कहा, आय वृद्धि से कंपनी का प्रदर्शन रहेगा उम्दा

₹ 2,232.90 पिछला बंद भाव
₹ 2,293.50 आज का बंद भाव
▲ 2.71 %

श्री सीमेंट

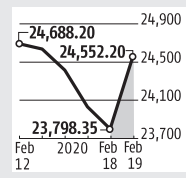

कंपनी का शेयर 27 मार्च से निफ्टी 50 सूचकांक में शामिल होगा

₹ 23,798.35 पिछला बंद भाव
₹ 24,552.20 आज का बंद भाव
▲ 3.17 %

वोडाफोन आइडिया

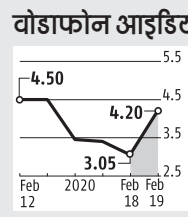

वायदा एवं विकल्प श्रेणी में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 3.05 पिछला बंद भाव
₹ 4.20 आज का बंद भाव
▲ 37.70 %

ग्रैन्यूल्स इंडिया

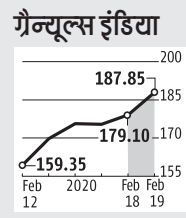

एपीआई कीमतों में तेजी की उम्मीद में 2020 में 50 फीसदी चढ़ा शेयर

₹ 179.10 पिछला बंद भाव
₹ 187.85 आज का बंद भाव
▲ 4.89 %

संक्षेप में

श्री सीमेंट में 700 करोड़ रुपये का निवेश मुमकिन

श्री सीमेंट के शेयर में बुधवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई क्योंकि एनएसई ने इस शेयर को निफ्टी-50 इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा की है। कंपनी का शेयर 2.6 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 24,406 रुपये पर बंद हुआ। एडलवाइस के विश्लेषकों का अनुमान है कि निफ्टी में शामिल किए जाने से इस शेयर में करीब 700 करोड़ रुपये का निवेश हो सकता है। कोलकाता की सीमेंट निर्माता इंडेक्स में येस बैंक की जगह लेगी। उधर, निफ्टी से हटाए जाने के कारण येस बैंक के शेयरों में 170 करोड़ रुपये की बिकवाली हो सकती है। निफ्टी इंडेक्स में यह बदलाव 27 मार्च से प्रभावी होगा। श्री सीमेंट का शेयर निफ्टी-50 इंडेक्स में सबसे महंगा शेयर होगा। निफ्टी में शामिल नेस्ले इंडिया के शेयर की कीमत अभी सबसे ज्यादा 16,758 रुपये है। *बीएस*

फोर्ड ने बीएस-6 मानक के साथ उतारे मॉडल

फोर्ड ने बुधवार को भारत चरण-6 के उत्सर्जन मानकों वाली अपनी कॉम्पैक्ट कार मॉडल फिगो, फ्रीस्टाइल और एस्पायर उतारीं। दिल्ली में इनकी शोरूम पर कीमत 5.39 लाख रुपये से लेकर 8.34 लाख रुपये के बीच है। फोर्ड इंडिया ने एक बयान में कहा कि तीनों मॉडलों में पेट्रोल और डीजल इंजन- दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध होंगे। इनके इंजन की क्षमता 1.2 लीटर से 1.5 लीटर होगी। कॉम्पैक्ट हैचबैक फिगो की कीमत 5.39 लाख रुपये से लेकर 7.85 लाख रुपये है। *भाषा*

ब्रिटेन में शुरू हुआ टाटा का नवाचार केंद्र

ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने आवागमन की भविष्य की स्वस्थ परियोजनाएं तैयार करने के लिए वारविक यूनिवर्सिटी में टाटा मोटर्स के जगुआर लैंड रोवर नवोन्मेष केंद्र की मंगलवार को औपचारिक शुरुआत की। यह केंद्र 15 करोड़ पाउंड के निवेश से तैयार हुआ है तथा यूरोप का सबसे बड़ा वाहन शोध एवं विकास संयंत्र है। नैशनल ऑटोमोटिव इनोवेशन सेंटर में ब्रिटेन और भारत के एक हजार शोधकर्ता, इंजीनियर और डिजायनर भविष्य के वाहन तैयार करने पर काम कर सकेंगे। *भाषा*

आईजीएल को बेहतर मार्जिन की आस

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 तक के लिए पूंजीगत खर्च की योजना बनाई

ज्योति मुकुल
नई दिल्ली, 19 फरवरी

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) अगले पांच साल में गैर-राष्ट्रीय राजधानी (एनसीआर) शहरों में अपने गैस वितरण नेटवर्क से राजस्व बढ़ाने की संभावना तलाश रही है। एनसीआर बाजार में एक्सक्लूसिविटी के नुकसान की आशंका से जूझ रही आईजीएल का कहना है कि उसके लिए एक्सक्लूसिविटी दर्जा खोने की तुलना में शुल्क की व्यवहार्यता ज्यादा महत्वपूर्ण होगी।

आईजीएल के प्रबंध निदेशक ई एस रंगनाथन के अनुसार, कंपनी के लिए गैस की कीमत प्रमुख चुनौती बनी हुई है न कि एक्सक्लूसिविटी। उन्होंने कहा, 'हमारा मार्जिन नियामक द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन निवेश पर उपयुक्त प्रतिफल मिलना चाहिए।'

एनसीआर बाजार कंपनी की वृद्धि का आधार रहा है, हालांकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा संचालित नीलामियों के तहत गैस वितरण व्यवसाय के लिए इस क्षेत्र से बाहर 6 भौगोलिक क्षेत्र उसके नेटवर्क में शामिल हुए हैं। रंगनाथन ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ एक साक्षात्कार में कहा, 'हमारे परिचालन क्षेत्र का दायरा बढ़कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 16 जिलों तक हो गया है। हमारी वृद्धि में इनका योगदान पांच साल में स्पष्ट रूप से दिखेगा।'

उन्होंने कहा, 'एनसीआर के अलावा, हमें बाजार तलाशना होगा और जागरूकता पैदा करनी होगी, क्योंकि मौजूदा समय में सिर्फ एनसीआर के आसपास के इलाकों में ही गैस इस्तेमाल के बारे में जागरूकता है। हमें वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ता जोड़ने होंगे।'

आईजीएल के लिए विपणन विशिष्टता का दर्जा दिल्ली में 2012 में ही समाप्त हो गया।

आईजीएल का लगभग 50 प्रतिशत पूंजीगत खर्च एनसीआर से बाहर होगा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 में 1,100 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021 में 1,400 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 के लिए 1,200 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की योजना बनाई है। अजमेर जैसे शहरों और आसपास के इलाकों में आईजीएल को आठ वर्षों में पाइप्ड गैस ग्राहकों की संख्या 100,000 हो जाने की संभावना है।

मौजूदा समय में आईजीएल के 12.4 लाख घरेलू ग्राहक हैं जबकि उसके वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या 4,000 तथा 2,500 है। कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाकर तीन साल में 20 लाख और आठ साल में 25 लाख करने का लक्ष्य रखा है।

कंपनी के राजस्व में मौजूदा समय में सीएनजी का 75 प्रतिशत का योगदान है और अगले पांच साल के लिए यह बरकरार रहने की संभावना है। उन्होंने कहा, 'सीएनजी व्यवसाय में 10 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है जो आगे भी बरकरार रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की पेशकश में ज्यादा तेजी नहीं आई है।'

हालांकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा बढ़ने से सीएनजी के लिए बाजार प्रभावित हो सकता है, और आईजीएल ने अपने सीएनजी स्टेशनों पर चार्जिंग पॉइंट लगाने की योजना तैयार की है। कंपनी के सभी नए सीएनजी स्टेशनों पर ई-चार्जिंग की व्यवस्था होगी। आईजीएल ने इन चार्जिंग पॉइंट के लिए दिल्ली में दो प्रमुख वितरण कंपनियों में से एक टाटा पावर के साथ समझौता किया है।

निवेश की तैयारी

फोटो: दलीप कुमार

- कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 में 1,100 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021 में 1,400 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 के लिए 1,200 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की योजना बनाई है
- कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले सभी नए सीएनजी स्टेशनों पर ई-चार्जिंग की व्यवस्था होगी

मंदी को मात दे रही सुजूकी मोटरसाइकल

शैली सेठ मोहिले
ग्रेटर नोएडा/मुंबई, 19 फरवरी

सुजूकी मोटर कंपनी की दोपहिया विनिर्माण इकाई सुजूकी मोटरसाइकल इंडिया की नजर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बिक्री में दो अंकों की वृद्धि पर है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि वह बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 7.5 फीसदी की वृद्धि के साथ चालू वित्त वर्ष को अलविदा करेगी।

कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि बर्गमैन स्ट्रीट, ऐक्सेस, जिक्सर श्रृंखला के मोटरसाइकल जैसे बीएस6 उत्सर्जन मानदंड वाले हाल में उतारे गए मॉडलों से बिक्री को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी मोटरसाइकल पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी।

हालांकि कमजोर आधार के साथ बिक्री में बढ़त ऐसे समय में दिख रही है जब अधिकतर दोपहिया विनिर्माताओं ने बिक्री में गिरावट दर्ज की है और उन्हें आगामी त्योहारी सीजन से पहले की तिमाहियों में बिक्री बढ़ने के आसार नहीं दिख रहे हैं।

सुजूकी मोटरसाइकल इंडिया के प्रबंध निदेशक कोईची हिराओ ने कहा कि अधिकतर प्रतिस्पर्धी कंपनियों के विपरीत हम आगे की राह को लेकर आश्वस्त हैं। जबरदस्त प्रतिस्पर्धा वाले इस बाजार में वर्षों के संघर्ष के बाद ऐक्सेस स्कूटर और जिक्सर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी के लिए स्थिति बदलती दिख रही है। फिलहाल इस बाजार में चार प्रमुख कंपनियों का वर्चस्व है।

भारत में वाहन बाजार काफी लंबी मंदी से जूझ रहा है लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान सुजूकी मोटरसाइकल की बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 10 महीनों के दौरान इस श्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 3.88 फीसदी हो गई जो वित्त वर्ष 2015-16 में 1.90 फीसदी थी। जबकि इस दौरान उसकी बिक्री 3.13 लाख वाहन से बढ़कर करीब 5.93 लाख वाहन हो गई।

कंपनी 7.5 फीसदी वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2020 को अलविदा करेगी, अगले वित्त वर्ष में 10 फीसदी वृद्धि पर नजर

स्मार्ट आईवियर श्रेणी में उतरने की तैयारी कर रही टाइटन फास्ट्रैक

समरीन अहमद
बेंगलूरु, 19 फरवरी

फास्ट्रैक रेफलेक्स के साथ स्मार्ट वियरेबल श्रेणी में दस्तक देने के तीन साल बाद टाइटन की सहायक इकाई फास्ट्रैक अब स्मार्ट आईवियर बाजार में दस्तक देने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, बेंगलूरु की कंपनी अगले महीने के अंत तक स्मार्ट ऑडियो सनग्लास को लॉन्च करने वाली है। इन धूप के चश्मों में इनबिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर होंगे जिसके जरिये उपयोगकर्ता फोन कॉल करने और संगीत सुनने में समर्थ होंगे। फास्ट्रैक वाइब नाम से यह उत्पाद दो वेरिएंट में उपलब्ध होगा। टाइटन ने इस बाबत जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया।

सूत्रों ने कहा, 'बाजार में कई स्मार्ट आईवियर कंपनियां मौजूद हैं लेकिन इस उत्पाद का यूएसपी कीमत के लिहाज से सस्ता होना है जो 3 हजार से 4 हजार रुपये के बीच होगी।' बॉश फ्रेम्स ऑडिया सनग्लास को भारत में पिछले साल जून में 21,900 रुपये की कीमत के साथ उतारा गया था।

विशेषज्ञों के अनुसार, टाइटन ने स्मार्ट वियरेबल उत्पादों की श्रेणी में खुद को एक अग्रणी कंपनी के तौर पर स्थापित किया है।

कमीशन भुगतान ढांचे पर सेबी की नजर

जश कृपलानी
मुंबई, 19 फरवरी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) म्युचुअल फंडों के निवेश के हिसाब से कमीशन भुगतान ढांचे पर नए सिरे से गौर कर सकता है।

इस मामले से अवगत लोगों के अनुसार, बाजार नियामक सबसे पहले कुछ म्युचुअल फंड योजनाओं में पहले वर्ष और बाद के वर्षों के दौरान दिए जाने वाले कमीशन में दरों में अंतर की जांच करेगा। सूत्रों ने कहा कि पहले वर्ष और बाद के वर्षों के दौरान दिए जाने वाले कमीशन में अंतर 45 से 50 आधार अंकों में था।

उद्योग प्रतिभागियों के अनुसार, फंड हाउसों द्वारा अग्रिम कमीशन को टालने और पहले साल में निवेश के हिसाब से अधिक भुगतान के जरिये प्रोत्साहन दिए जाने के बाद इस प्रकार की योजनाओं में अंतर दिखने लगा। एक फंड हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अग्रिम कमीशन के अभाव में कुछ फंड हाउस ने पहले साल निवेश के हिसाब से दिए जाने वाले अपने कमीशन को समायोजित किया।' विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की पहल से अग्रिम कमीशन को रोकने का उद्देश्य धूमिल होगा।

एक फंड मैनेजर ने कहा, 'पोर्टफोलियो मंथन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अग्रिम कमीशन को खत्म किया गया था। खास तौर पर बड़े वितरक अग्रिम कमीशन से फायदे के लिए अपने ग्राहकों को इन योजनाओं के तहत रखा है।।'

- पहले साल और बाद के वर्षों की कमीशन दरों में अंतर की जांच कर रहा बाजार नियामक
- म्युचुअल फंड योजनाओं की बिक्री के लिए वितरकों को अग्रिम कमीशन का एकमुश्त भुगतान के तौर पर किया गया
- बाजार नियामक ने डायरेक्ट प्लान के जरिये आने वाले निवेशकों पर अनुचित तरीके से अधिक शुल्क थोपने के लिए फंड हाउसों को लताड़ा है

म्युचुअल फंड योजनाओं की बिक्री के लिए वितरकों को अग्रिम कमीशन का भुगतान एकमुश्त भुगतान के तौर पर किया गया। सेबी की 19 सदस्यीय म्युचुअल फंड सलाहकार समिति के एक सदस्य ने कहा, 'निवेश के हिसाब से भुगतान का मॉडल अभी भी अग्रिम भुगतान के मुकाबले बेहतर है क्योंकि उसे निवेशक पोर्टफोलियो के लिए स्पष्ट प्रोत्साहन है।' निवेश के हिसाब से कमीशन में अंतर के बारे में सेबी की पूर्णकालिक सदस्य माधवी पुरी बुच ने कहा, 'हाल में यह हमारे संज्ञान में आया है कि निवेश के हिसाब से कमीशन का ढांचा किस प्रकार तैयार किया गया है। हम इस पर नए सिरे से गौर करेंगे।' वह सोमवार को सेबी की बोर्ड बैठक के दौरान बोल रही थीं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान म्युचुअल फंड उद्योग में काफी बदलाव आया है ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा और निवेश लागत को घटाया जा सके।

बाजार नियामक ने डायरेक्ट प्लान के जरिये आने वाले निवेशकों पर अनुचित तरीके से अधिक शुल्क थोपने के लिए फंड हाउसों को लताड़ा है। बाजार नियामक ने सभी योजनाओं में फंड हाउसों द्वारा योजना से संबंधित खर्च अनिवार्य दिखाना अनिवार्य कर दिया है ताकि अलग निवेश मार्ग के जरिये आने वाले निवेकों की लागत का वहन कुछ खास निवेशक वर्ग को न करना पड़े।

बाजार नियामक द्वारा अग्रिम कमीशन को हटाए जाने के बाद वर्ष 2018-19 में म्युचुअल फंडों द्वारा कमीशन एवं अन्य वितरण खर्च के जरिये वितरकों को होने वाला भुगतान 7 फीसदी घटकर 7,938 करोड़ रुपये रह गया।

टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन होंगे सस्ते

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 19 फरवरी

वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स अप्रैल से अपने वाणिज्यिक वाहनों के दाम घटाएगी। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि नए उत्सर्जन मानदंड बीएस6 के लागू होने के बाद टाटा मोटर्स अपने मझोले एवं भारी वाणिज्यिक वाहनों (एमएचसीवी) के दाम घटाने की योजना बना रही है।

टाटा मोटर्स के अध्यक्ष (वाणिज्यिक वाहन कारोबार) गिरीश वाघ के अनुसार, ट्रक बनाने वाली यह कंपनी सख्त उत्सर्जन मानदंडों को एक अवसर मान रही है। कंपनी पूरी मूल्य श्रृंखला पर नए सिरे से गौर करने के साथ-साथ लागत को युक्तिसंगत बनाने और नए मॉडल उतारने के लिए काम कर रही है ताकि उद्योग में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया जा सके।

वाघ ने कहा, 'बाजार की अग्रणी कंपनी होने के नाते हम मूल्य ढांचे में काफी हद कमी लाएंगे। ऐसा करने के लिए यह सही समय है।' उन्होंने कहा कि कंपनी तिमाही दर तिमाही छूट को वापस ले रही है। उन्होंने कहा, 'फिलहाल जिस तरह की छूट दी जा रही है उससे कोई भी खुश नहीं है।' हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि अप्रैल के बाद भी छूट काफी रहेगी। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग (आईएफटीआरटी) के वरिष्ठ फेलो एसपी सिंह ने कहा, 'मौजूदा परिस्थिति में कोई भी नैतिक आधार पर ऐसा नहीं कर सकता है।' उन्होंने कहा कि जमीनी वास्तविकता काफी अलग है। छूट लगातार ऊंची रहेगी और यह आगे भी बरकरार रह सकती है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही बिक्री काफी कमजोर रहेगी।

शेयरखान के विश्लेषक भरत ज्ञानी ने भी इससे सहमति जताई। उन्होंने कहा, 'मांग में गिरावट दो अंकों में दिख रही है और कंपनियां किसी भी कीमत पर बाजार हिस्सेदारी हासिल करना चाहती हैं। बीएस6 उत्सर्जन मानदंड लागू होने से विनिर्माताओं के लिए लागत में 10 से 11 फीसदी का इजाफा होगा। कमजोर मांग को देखते हुए वे इसका बोझ खरीदारों के कंधों पर नहीं डाल सकते। इससे उनके मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा।'

ज्ञानी ने कहा, 'यहां तक कि ऊपरी चक्र के दौरान भी छूट में वृद्धि हुई। हालांकि लागत में कटौती से मदद मिलेगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि छूट में कोई नरमी आएगी।'

अशोक लीलैंड के प्रबंधन ने निवेशकों से बातचीत में कहा है कि बाजार में छूट हमेशा बरकरार रहेगी। यह औसतन 5 लाख रुपये से बढ़कर 5.25 लाख रुपये हो गई है। आर्थिक सुस्ती और खपत में नरमी के अलावा नियामकीय बदलावों के कारण एमएचसीवी की बिक्री कमजोर हो गई है। ऐसे में विनिर्माताओं के लिए वाहन लागत का 15 से 20 फीसदी तक भारी छूट देने की मजबूरी हो गई है। बीएस6 उत्सर्जन मानदंड के लागू होने पर छूट देने का चलन और बढ़ेगा। इन वाहनों की बिक्री पिछले डेढ़ साल से घट रही है। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम के अनुसार, फरवरी में इन वाहनों की बिक्री 9.81 फीसदी घटकर 30,831 वाहन रह गई। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान इसमें करीब 41 फीसदी की गिरावट आई है।

जून में बिक्री में गिरावट शुरू होने के बाद से ही टाटा मोटर्स अपने ग्राहकों के साथ काफी तालमेल बिठा रही है। वाघ ने कहा कि कंपनी ने ग्राहकों की परेशानी समझने की कोशिश की और कुछ इनपुट बीएस6 मॉडलों में शामिल किया। उन्होंने कहा, 'हमने पूरी श्रृंखला में बदलाव की है। इस प्रक्रिया की शुरुआत उसी समय शुरू हो गई थी जब बीएस6 के लिए बदलाव किया जा रहा था।'

मुफ्त सैंपल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट न देने का मामला न्यायालय में

कंपनियों द्वारा मुफ्त सैंपल या उपहार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दिए जाने से इनकार के मसले पर गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड को नोटिस भेजा है। कंपनियों द्वारा दवा जैसे क्षेत्रों में मुफ्स सैंपल या उपहार दिया जाना आमतौर पर प्रचलन में है।

याची ने दो सरकारों व अन्य के खिलाफ याचिका दायर कर केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) (एच) और इससे संबंधित अधिसूचनाओं को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की है, जिनमें तोहफों और मुफ्त नमूनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से मना किया गया है। इस धारा में उन वस्तुओं की सूची दी गई है, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है, जैसे किराये पर कैब। बहरहाल इस धारा में तोहफों व नमूनों का खास उल्लेख नहीं किया गया है। इसे लेकर भ्रम तब पैदा हुा जब दवा सहित विभिन्न कंपनियों के उपहार और मुफ्त नमूनों पर क्रेडिट रोक दिया गया। *बीएस*

डिफॉल्ट रेटिंग पर समिति के सवाल

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 19 फरवरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने चूक की परिभाषा की समीक्षा को लेकर बेरुखी दिखाई है। यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) द्वारा कंपनियों के वाणिज्यिक कागजातों की रेटिंग का मुख्य मानक है। संसदीय समिति ने भी मानकों में ढील देने पर जोर दिया है।

सोमवार को अधीनस्थ कानून पर बनी संसदीय समिति ने एक बैठक की और नियामक व वित्त मंत्रालय के समक्ष चूक के मानदंडों में ढील देने पर जोर दिया, जिसके कारण बैंक कम रेटिंग वाली फर्मों को धन मुहैया नहीं करा पाते हैं। इसके अलावा फर्मों को चूक की श्रेणी में डाले जाने संबंधी इस तरह के वर्गीकरण से वे ऋण पत्रों से भी बाहर नहीं निकल पातीं।

अगर बैंकों के ऋण से तुलना की जाए तो वाणिज्यिक पत्र/ऋण पत्र कंपनियों के धन जुटाने के प्रिय माध्यम होते हैं। इससे कंपनियों को अपनी कम अवधि की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। सूत्रों के मुताबिक समिति की राय है कि इस तरह के प्रतिबंधों का व्यापक दुष्प्रभाव है।

सूत्रों ने कहा कि कंपनी को जब एक बार 'चूक' या खराब रेटिंग की श्रेणी में डाल दिया जाता है तो उन्हें बैंकों से धन नहीं मिलता। इस बैठक में शामिल लोगों ने कुछ उदाहरण भी दिए, जिनमें बैंकों के कड़े रुख के कारण कंपनियां बर्बाद हो गईं।

रिजर्व बैंक के अलावा इस बैठक में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), वित्तीय सेवा विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व रेटिंग फर्मों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

बैठक में रेटिंग की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख करने के साथ इस पर भी चर्चा हुई कि अगर किसी कंपनी को अगर एक बार नीचे की श्रेणी में डाल दिया जाता है तो उसे ऊपर आने में बहुत वक्त लगता है। चूक से किसी ग्रेड में ऊपर की ओर बदलाव करने में कम से कम 90 दिन का वक्त लगता है, जबकि रेटिंग डिफॉल्ट के दर्जे से निवेश ग्रेड में रेटिंग वापस आने में कम से कम एक साल लग जाते हैं।

सीआरए के दिशानिर्देशों के मुताबिक बीबी और इसके नीचे की ग्रेडिंग को अटकल वाली ग्रेडिंग माना जाता है और बीबीबी के ऊपर की ग्रेडिंग को निवेश ग्रेड माना जाता है। रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश उपचार की अवधि की परिभाषा को लेकर है, जबकि उपचार की अवधि का खाका सेबी के नियमों के अंतर्गत आता है।

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर पूंजी बाजार के नियामक ने भी विभिन्न इंस्ट्रूमेंट में चूक की अपनी परिभाषा दी है। उदाहरण के लिए सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, बॉन्डों, सावधि जमाओं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और वाणिज्यिक पत्र के मामलों में पुनर्भुगतान की अवधि से अगर एक दिन भी और एक रुपये की भी (मूलधन या ब्याज में) चूक होती है तो उसे डिफॉल्ट माना जाता है।

खरीदार के क्रेडिट, पैकिंग क्रेडिट और बिल खरीद के मामले में 30 दिन से ज्यादा बकाया होने की स्थिति में चूक माना जाता है। रेटिंग एजेंसियां सामान्यतया एएए (समय से कर्ज भुगतान के मामले में सर्वाधिक सुरक्षित) से लेकर डी (चूक या जल्द चूक की संभावना) के बीच रेटिंग स्केल का पालन करती हैं।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के लिए रेटिंग एजेंसियों पर बड़े पैमाने पर शिथिल नीतियां अपनाने और उपेक्षा के आरोप लगते हैं। एएए रेटिंग के आधार पर वाल स्ट्रीट के बैंकरों ने मॉर्गेज बॉन्डों और डेरिवेटिवव्स में अरबों डॉलर लगाए थे।

आईएलऐंडएफएस के मामले में रेटिंग एजेंसियों इंडिया रेटिंग्स, इक्रा और केयर ने सितंबर 2018 में कंपनी के चूक करने के महज एक महीने पहले एएए और एए प्लस रेटिंग दी थी। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के 25वें संस्करण में रिजर्व बैंक ने रेटिंग को लेकर चेतावनी दी थी।

रिजर्व बैंक रुख पर कायम

संसद की समिति ने सोमवार को सेबी, वित्त मंत्रालय व बैंक के अधिकारियों से भी की मुलाकात

90 दिन लग जाते हैं रेटिंग के बदलाव में

1 दिन या 1 रुपये भी मूलधन या ब्याज में निर्धारित भुगतान तिथि से चूक करने पर कंपनी हो जाती है डिफॉल्टर

- रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर पूंजी बाजार नियामक ने भी बनाई है चूक की परिभाषा
- इससे कंपनियां संकट में फंस रही हैं

ऐच्छिक होगी फसल बीमा योजना

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 19 फरवरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ऋणग्रस्त किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को ऐच्छिक करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही इसे किसानों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के लिए इसमें कई और बदलाव किए गए हैं। तीन साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को बड़े ही जोर शोर से शुरू किया था। इस योजना की काफी आलोचना भी होती रही है।

खरीफ सत्र 2020 यानी अगले खरीफ सीजन से इसे ऋणग्रस्त किसानों के लिए ऐच्छिक कर दिया जाएगा। इसे आरंभ किए जाने के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने योजना के प्रीमियम सब्सिडी के तौर पर करीब 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक फिलहाल 58 फीसदी किसान ऋणग्रस्त हैं और शेष 42 फीसदी किसान इससे मुक्त हैं।

दिलचस्प है कि ऋणमुक्त किसानों के लिए इस योजना में शामिल होना शुरू से ही ऐच्छिक है इसके बावजूद इसमें उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है जो दिखाता है कि किसानों के एक बड़े वर्ग में इस योजना की स्वीकार्यता है।

आंकड़ों से पता चलता है कि खरीफ सीजन 2016 मे करीब 1.02 करोड़ कर्ज मुक्त किसान इस योजना में शामिल हुए जो 2018 के खरीफ सीजन में बढ़कर 1.24 करोड़ पर पहुंच गया यह करीब 22 फीसदी की उछाल दर्शाता है। रबी सीजन 2016-17 में पीएमएफबीवाई के तहत कुल पंजीकरण में कर्ज मुक्त किसानों की हिस्सेदारी 0.34 करोड़ थी जो रबी सीजन 2018-19 में बढ़कर 0.79 करोड़ हो गई इस प्रकार इसमें 132 फीसदी की वृद्धि हुई। हालांकि, योजना के तहत कुल नामांकन में कमी आती रही।

अन्य फैसले

- **डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी, इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा**
- **डेयरी किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सहायता दो से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत की गई**
- **अधिकार संपन्न प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंजूरी**
- **सहायक प्रजनन तकनीक विधेयक को मंजूरी**
- **22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी। पूर्व विधि आयोग का कार्यकाल इस वर्ष अगस्त में समाप्त हो रहा है**

मोदी की आर्थिक नीतियों पर मनमोहन का हमला

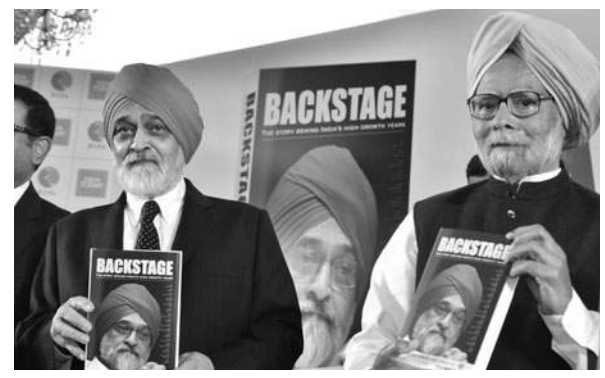

मोंटेक सिंह अहलूवालिया की पुस्तक बैकस्टेज का विमोचन करते पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह *फोटो-संजय शर्मा*

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 19 फरवरी

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि यह सरकार आर्थिक सुस्ती को स्वीकार भी नहीं कर रही है जिससे अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक पांच लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचा पाना महज कल्पना ही रह जाएगी।

मनमोहन ने योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की किताब के विमोचन कार्यक्रम में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'आज एक ऐसी सरकार है जो आर्थिक सुस्ती जैसे शब्द को स्वीकार भी नहीं करती है। अगर आप समस्या को नहीं मानते हैं तो आप उस समस्या को दूर करने के उपाय भी नहीं उठा सकते हैं।' डॉ सिंह ने कहा कि वास्तविक राजकोषीय घाटा नौ फीसदी के स्तर तक पहुंच चुका है जो सालाना नौ-दस फीसदी आर्थिक वृद्धि के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि आठ फीसदी की वृद्धि दर हासिल करना संभव है लेकिन इसके लिए राजकोषीय नीति और साहसिक कर सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को तीन साल में दोगुना करने का लक्ष्य भी हासिल नहीं किया जा सकता है।

'फ्लिपकार्ट, फोन पे के प्रदर्शन से खुश'

वालमार्ट इंटरनैशनल की सीईओ जूडिथ मैकेन्ना ने कहा है कि कंपनी भारत की अपनी कंपनियों ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और डिजिटल पेमेंट फर्म फोन पे और ऑनलाइन फैशन रिटेलर मिंत्रा के प्रदर्शन से खुश है।

उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने अमेरिकी खुदरा दिग्गज की उम्मीदों के अनुरूप काम किया है। खासकर फ्लिपकार्ट का विशेष उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स दिग्गज के सक्रिय ग्राहकों की संख्या 45 प्रतिशत बढ़ी है, वहीं प्रति ग्राहक लेन देन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 1 अरब से ज्यादा विजिट हुई है।

आर्कंसास के बेंटनविले की कंपनी फ्लिपकार्ट के माध्यम से मुकाबला कर रही है। *बीएस*

इंडिगो, स्पाइसजेट व अन्य की मिलीभगत के साक्ष्य नहीं

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जांचकर्ताओं को देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो व 4 अन्य प्रतिस्पर्धी विमान कंपनियों को टिकट के दाम तय करने में मिलीभगत के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस मामले से जुड़े 3 सूत्रों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी है।

सीसीआई ने कुछ मार्गों पर इंडिगो, स्पाइसजेट, गोएयर और सरकारी कंपनी एयर इंडिया और अब बंद हो चुकी जेट एयरवेज के एकसमान किराये की पेशकश को लेकर शिकायत मिलने पर प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधि के आरोपों की जांच 2015 में शुरू की थी। सीसीआई की जांच में एयरलाइंस के टिकट के दाम तय करने के तरीकों की जांच शामिल थी। तीन सूत्रों ने कहा कि जांच में पाया गया कि सभी 5 एयरलाइंस स्वतंत्र रूप से काम कर रही थीं। एक सूत्र ने कहा, 'कार्टलाजेशन का कोई सीधा साक्ष्य नहीं मिला है।' उन्होंने कहा कि जांच में कीमतें तय करने को लेकर एयरलाइंस के अधिकारियों के बीच किसी चर्चा के भी सबूत नहीं मिले हैं। *रॉयटर्स*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 4

अपर्याप्त विधान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यह कृषि-रसायन क्षेत्र के अंशधारकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। यह विधेयक 12 वर्ष की लंबी अवधि में तैयार किया गया है और इस प्रक्रिया में संसद की स्थायी समिति तथा अन्य स्रोतों से मिली जानकारियों का भी इस्तेमाल किया गया है। किसानों के हितों की रक्षा करने के प्रयास में विधेयक उद्योग जगत के खिलाफ झुकाव वाला बन गया है। जाली, खराब गुणवत्ता वाले या निष्प्रभावी कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की तेज क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में 50,000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष तैयार करने की बात कही गई है। सुझाव है कि इस फंड के लिए राशि डिफॉल्ट करने वाली कीटनाशक कंपनियों और केंद्र तथा राज्य सरकारों से सहयोग से जुटाई जाएगी। प्रतिबंधित या खराब गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की आपूर्ति पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने तथा तीन से पांच वर्ष के कारावास का प्रस्ताव है। फिलहाल जुर्माने की राशि केवल 2,000 रुपये और तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। उत्पादन, व्यापार और कीटनाशकों के प्रयोग को केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड की सहायता से विनियमित करने की बात कही गई है। इस बोर्ड में केंद्र, राज्य, किसान तथा अन्य अंशधारक होंगे। विधेयक की अन्य उल्लेखनीय बातों में पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के अनुकूल ऑर्गेनिक कीटनाशकों की बात शामिल है। कीटनाशक क्षेत्र में लंबे समय से एक प्रभावी नियामकीय व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी क्योंकि सन 1968 का पुराना कीटनाशक अधिनियम अक्षम साबित हुआ।

कीटनाशक उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ जिसके चलते अनेक फर्जी, खराब गुणवत्ता वाले और खतरनाक रसायन चलन में आ गए। हालांकि केवल 300 के करीब कीटनाशक ही देश में उत्पादन एवं इस्तेमाल के लिए पंजीकृत हैं लेकिन प्रचलित रसायनों की वास्तविक तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना पंजीयन के भी इनका उत्पादन और बिक्री की जा रही है। कई खतरनाक कीटनाशक, जिन्हें विदेशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, उनका भारत में इस्तेमाल जारी है। इसके कारण हर वर्ष सैकड़ों की तादाद में खेतों में काम करने वाले लोगों की जान चली जाती है।

आशा है कि नया कानून ऐसे घातक रसायनों के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाएगा और मानकों को कड़ा करेगा। बहरहाल, प्रस्तावित कानून के कारण कीटनाशक उद्योग के कुछ हलकों के मन में आशंकाएं भी उत्पन्न हुई हैं। शोध और विकास से जुड़ी 16 फसल विज्ञान कंपनियों के संगठन द क्रॉपलाइफ इंडिया ने पहले ही यह मांग की है कि विधेयक को संसद की प्रवर समिति के पास भेजा जाए और इस क्षेत्र के विभिन्न अंशधारकों के साथ नए सिरे से मशविरा किया जाए। उसने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के लागू होने की व्यवस्था समाप्त करके कृषि कच्चे माल के निर्माण का अपराधीकरण समाप्त करने की भी वकालत की है। दलील यह है कि उक्त प्रावधान से निवेश को लेकर नकारात्मक माहौल बनता है।

विधेयक को मंजूरी के लिए भेजने से पहले सार्वजनिक मशविरा अपनाकर कई कमियों से बचा जा सकता था। विधेयक के बारे में जो सीमित जानकारी सामने आई उसके मुताबिक इसमें कृषि उपज में कीटनाशकों की मौजूदगी की जांच पर ज्यादा जोर देने की बात शामिल होनी है क्योंकि वह मानव जीवन, पालतू पशुओं और वन्य जीवों के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर वायु, मृदा और जल प्रदूषण की वजह बन रहा है। ऐसे में प्रस्तावित कानून में केवल कम नुकसानदेह कीटनाशकों की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि किसानों को इनके सावधानीपूर्ण प्रयोग की बात समझाने की बात शामिल होनी चाहिए ताकि खेतों में इनके अवशेष न बचें।

अजय मोहंती

वुहान संकट का वैश्विक प्रभाव

कोरोनावायरस लोगों के स्वास्थ्य पर कितना असर डालेगा यह कुछ दिन में पता चल जाएगा लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव तो नजर भी आने लगा है। विस्तार से बता रहे हैं **आकाश प्रकाश**

चीन के बाहर कोरोनावायरस का आर्थिक प्रभाव अब तक सीमित है लेकिन इसमें दो राय नहीं कि यह चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। वैश्विक वृद्धि के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।

चीन में कोरोनावायरस के रोज सामने आने वाले नए मामलों की तादाद जहां 5,000 से घटकर 2,000 रह गई है, वहीं अब तक इस बीमारी से 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है तथा 75,000 संक्रमित हो चुके हैं। चीन के बाहर इसका विस्तार सीमित है हालांकि मीडिया में ऐसी डराने वाली खबरें आती रही हैं कि वैश्विक आबादी का दो तिहाई हिस्सा इसकी चपेट में आ सकता है। अगले 7 से 10 दिन अहम होंगे क्योंकि 10 करोड़ से अधिक चीनी कर्मचारी दोबारा काम पर लौटेंगे। क्या फैक्टरियों के शुरू होने के बाद संक्रमण का नया दौर सामने आ सकता है?

चीन की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में सोचते हुए हमें तीन अन्य पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। पहला, स्वास्थ्य के जोखिम। दुनिया भर में कोरोनावायरस को लेकर बहुत अधिक जोखिम है लेकिन चीन के बाहर इसका प्रभाव सीमित रहना चाहिए। यह काफी हद तक चीन में सीमित है। 30 अन्य देशों में केवल 500 मामले सामने आए हैं। चीन में भी एक खास भूभाग के बाहर पीड़ितों की तादाद कम हो रही है। चीन के बाहर केवल पांच लोगों की मौत हुई है। यह बीमारी व्यापक संक्रमण लेकिन कम मृत्यु दर वाली प्रतीत हो रही है।

अगले सप्ताह चीन की फैक्टरियों में काम शुरू हो जाएगा और तब इस वायरस के वैश्विक प्रभाव का आकलन करना अहम होगा।

आर्थिक प्रभाव की बात करें तो मौजूदा तिमाही निस्संदेह चीन की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बट्टे खाते में जाएगी। कारों और अन्य टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री में 20 से 40 फीसदी की गिरावट देखने को मिलेगी। परिसंपत्ति लेनदेन में भी रुकावट आएगी। इकलौती बचाव वाली बात यह है कि अवकाश के कारण हर वर्ष जनवरी-फरवरी महीने में कारोबार धीमा रहता है। अधिकांश संयंत्र सोमवार को शुरू होने थे लेकिन यात्रा प्रतिबंध और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी से अनिश्चितता पैदा हुई है। तमाम फैक्टरियां या तो बंद हैं या उनमें आंशिक रूप से काम हो रहा है क्योंकि मजदूर वापस नहीं आ सके हैं। चीन की सबसे बड़ी नियोक्ता फॉक्सकॉन की एक इकाई बंद है और शेनझेन और झेंगझाऊ में उसके संयंत्र आधे कर्मचारियों के साथ चल रहे हैं। चीन की सरकार ने वायरस का प्रसार रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं वे अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुबेई प्रांत जहां बीमारी शुरू हुई वहां चीन के वाहन उत्पादन का 9 फीसदी तथा बड़ी तादाद में कलपुर्जों का उत्पादन होता है। वैश्विक वाहन आपूर्ति शृंखला हुबेई की बंदी से सबसे अधिक प्रभावित हुई है।

चीन के संपत्ति बाजार पर भी इसका बहुत बुरा असर होगा। परिसंपत्ति की खरीद बिक्री के लिए आमने-सामने बात करनी होती है। चीन में इन दिनों यह संभव नहीं है। चीन के 60 से अधिक शहरों में संपत्ति के लेनदेन पर प्रतिबंध है। यही वजह है कि परिसंपत्ति बाजार ठप पड़ा है।

बिक्री को काफी नुकसान हुआ है और अचल संपत्ति का वित्तीय बाजार आज काफी सख्त है। प्रमुख आशंका यह है कि बिक्री में ऐसी भारी गिरावट के बाद अधिकांश परिसंपत्ति डेवलपरों की स्थिति कमजोर होगी क्योंकि नए निर्माण नहीं हो रहे। यही बात समूचे चीनी उद्योग जगत पर लागू होती है। बिक्री और उत्पादन को लगा मौजूदा झटका दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है।

वायरस का प्रसार रोकने और अर्थव्यवस्था को धीमा होने से बचाने के बीच संतुलन कायम करने के लिए चीन की सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी न करें। यानी ज्यादातर कंपनियां लागत में कमी नहीं कर पाएंगी। इसका असर नकदी की स्थिति पर पड़ेगा। हालांकि वहां की केंद्र सरकार बैंकों से निजी कंपनियों को ऋण दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है लेकिन बैंक इच्छुक नहीं लग रहे। ऋण की चिंता बढ़ने पर हमें आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट डिफॉल्ट भी देखने को मिल सकते हैं।

वैश्विक प्रभाव की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र भी प्रभावित होगा। वैश्विक पर्यटन व्यय का 20 फीसदी चीन में खर्च होता है और 30 से 50 फीसदी एशिया में। इन दिनों इस क्षेत्र के अधिकांश देशों ने चीन को जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। पर्यटन में मंदी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी।

तेल कीमतें पहले ही अपने अल्पावधि के उच्चतम स्तर से 20 फीसदी कम हो चुकी हैं। अधिकांश जिंस कीमतों में भी 10 से 15 फीसदी की गिरावट आई है। भारत इसका लाभ उठा सकता है। तेल कीमतों का सीधा संबंध मुद्रास्फीतिक अनुमानों से है, इसलिए दुनिया भर में केंद्रीय बैंक मौद्रिक राहत दे सकते हैं। यानी एक बार फेडरल रिजर्व के शुरुआत करने के बाद आर्थिक दृष्टि से बुरी खबर बाजार के लिए अच्छी खबर में तब्दील जो जाएगी।

पश्चिमी दुनिया के कई मीडिया संस्थानों ने कहा है कि चीन में कोरोनावायरस का प्रकोप तत्कालीन सोवियत संघ के चेर्नोबिल की तरह है। चीन के केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही यह माहौल बना दिया है कि कैसे उसने मामले की गंभीरता का पता लगते ही निर्णायक कदम उठाए। ज्यादातर जिम्मेदारी वुहान और हुबेई के स्थानीय नेतृत्व पर छोड़ दी गई। समूचे हुबेई प्रांत को बंद करने और 6 करोड़ लोगों को अलग-थलग करने की घटना को प्रमुखता से प्रचारित किया गया कि कैसे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णायक भूमिका निभाई।

इसके बावजूद यह सवाल बना रहेगा कि इस बीमारी के बारे में और इसकी गंभीरता के बारे में कब और कितनी जानकारी सामने आई। यह भावना भी बनी रहेगी कि चीन वैश्विक आर्थिक तंत्र का विश्वसनीय सदस्य नहीं है। यह अविश्वसनीयता उसके अस्पष्ट राजनीतिक तंत्र और आंतरिक संवाद में पारदर्शिता की कमी के रूप में सामने आएगा। विश्वास की इस कमी और बीते 18 महीनों के दौरान चीन-अमेरिका कारोबारी युद्ध के दौरान सामने आई कठिनाइयों के मद्देनजर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर कार्य विस्तार जारी रखेंगी। इसका सबसे अधिक लाभ वियतनाम को मिलेगा।

वैश्विक बाजार आश्वस्त रहते आए हैं। उन्हें 2003 में सार्स की बीमारी का दौर याद आ रहा है जब एशियाई परिसंपत्तियों की खरीद आसान हो गई थी। मुझे उम्मीद है कि इतिहास खुद को दोहराएगा और छह महीने में लोग सब भूल जाएंगे। बहरहाल, आश्वस्ति और एकतरफा पोजिशनिंग को देखते हुए कहा जा सकता है कि सावधानी बरतना ज्यादा उचित होगा। सस्ती हेजिंग पर भी विचार किया जाना चाहिए।

`विवाद से विश्वास' करदाताओं के लिए हो सकती है निराशाजनक

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

कर विभाग को एक ऐसी व्यवस्था कायम करने पर ध्यान देना चाहिए जो विवाद न खड़े करती हो और मौजूदा विवादों को कई वर्षों तक लटकाने की इजाजत न दे। `विवाद से विश्वास' योजना से सरकार को एकबारगी कर राजस्व का पुलिंदा मिल सकता है। लेकिन महज एक बार होने वाले विनिवेश प्राप्तियों की तरह यह लाभ भी तब तक कायम नहीं रहेगा जब तक कराधान प्रणाली में टिकाऊ सुधार नहीं लागू किए जाते हैं और विवादों का जल्द समाधान नहीं तलाशा जाता है।

प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों से जुड़ी मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की नई पहल ने करदाताओं के बीच उम्मीद जगाई है। तमाम अदालतों और अपील अधिकरणों में ऐसे करीब 4.83 लाख मुकदमे लंबित चल रहे हैं। लेकिन 'विवाद से विश्वास' नाम की यह योजना ऐसे तमाम करदाताओं के बीच बड़ी निराशा का सबब बन सकती है।

अगर कोई करदाता अपना मुकदमा हार चुका है और उसने अपील की हुई है तो इस योजना के तहत वह विवादित राशि का 100 फीसदी (जुर्माना एवं ब्याज छोड़कर) चुका कर मामले का निपटारा कर सकता है। इस तरह यह योजना कई करदाताओं के लिए विवाद को खत्म कर कर विभाग से मुक्ति का रास्ता दिखा सकती है। इसका मतलब है कि विवाद से विश्वास की तरफ बढ़ा जा सकता है।

लेकिन अगर कोई करदाता मुकदमा जीत चुका है और उसके खिलाफ कर विभाग ने अपील की हुई है तो इस योजना के तहत वह विवादित रकम का 50 फीसदी (जुर्माने एवं ब्याज के बगैर) भुगतान कर विवाद का निपटान करा सकता है। इस तरह की स्थिति में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आखिर निचली अदालत में मुकदमा जीत चुके करदाता को विवादित रकम का आधा हिस्सा चुकाने को क्यों तैयार होना चाहिए?

कर विभाग इस बात के लिए खासा चर्चित है कि किसी भी तरह के कर विवाद में वह हार मिलने पर अपील में चला जाता है। लिहाजा मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति को यह देखना होगा कि अपील पर लंबे समय तक खिंचने वाली अदालती कार्यवाही का सामना करने से कहीं बेहतर आधी रकम चुकाना है या नहीं। यह बात हालात को अधिक जटिल बना देती है कि कर विभाग के जिम्मे अब चालू वित्त वर्ष के बाकी बचे हफ्तों में बड़ा राजस्व संग्रह लक्ष्य को पूरा करना है। डर है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर विभाग कहीं करदाताओं पर यह अवांछित दबाव न डालने लगे कि वे इस योजना के तहत लंबित मामलों का निपटारा करें। इस तरह सरकार को वांछित अतिरिक्त राजस्व मिल जाएगा और विवाद से विश्वास योजना भी सफल हो जाएगी।

लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह कर विवादों की बड़ी समस्या को खत्म कर देगा जिससे बकाया कर संग्रह बढ़ेगा। पिछले 10 वर्षों में बकाये कर की समस्या बिगड़ती चली गई है। वित्त वर्ष 2009-10 में विवादित कर मामलों एवं गैर-विवादित कर मामलों को मिलाकर प्रत्यक्ष कर बकाये का कुल मूल्य 1.1 लाख करोड़ रुपये ही था जो केंद्र के 6.24 लाख करोड़ रुपये के सकल कर संकलन का महज 17.5 फीसदी है। वर्ष 2018-19 में सकल कर संग्रह में ऐसे बकाया कर की हिस्सेदारी तीव्र वृद्धि के साथ 45 फीसदी बढ़ गई। कुल 20.8 लाख करोड़ रुपये के सकल कर संग्रह में प्रत्यक्ष कर बकाया करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये रहा।

कर बकाया का बढ़ता बोझ

यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मनमोहन सरकार ने प्रत्यक्ष कर के मद में बकाये को अपने शासन के अंतिम वर्ष में बढ़कर 42 फीसदी तक बढ़ने दिया जबकि वर्ष 2004-05 में यह सकल कर संग्रह का 17.5 फीसदी ही था। मोदी सरकार के आने के बाद कर बकाये की बढ़त पर लगाम लगी लेकिन इसने उसे नीचे लाने की खास कोशिश नहीं की। यह 2015-16 में 45 फीसदी से भी अधिक बढ़ गया। निश्चित रूप से, कुछ कदमों से बकाया कर में 2016-17 के दौरान 43 फीसदी और 2017-18 में 38 फीसदी की तीव्र गिरावट आई थी लेकिन 2018-19 में यह एक बार फिर से 45 फीसदी से अधिक बढ़ गया।

हमें ध्यान रखना होगा कि इस बकाये कर का बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष कर विवादों की वजह से है। सकल कर संग्रह में गैर-विवादित प्रत्यक्ष कर मामलों के चलते बकाये कर का हिस्सा पिछले 10 वर्षों में कमोबेश अपरिवर्तित रहा है। वर्ष 2009-10 में यह 6.88 फीसदी था जबकि 2018-19 में यह 6.66 फीसदी रहा। यह समस्या खड़ी होने की मुख्य वजह यह रही है कि सकल कर संग्रह में विवादित कर मामलों का हिस्सा इस दौरान 11 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी बढ़ गया।

हालांकि कर विभाग को एक ऐसी व्यवस्था कायम करने पर ध्यान देना चाहिए जो विवाद न खड़े करती हो और मौजूदा विवादों को कई वर्षों तक लटकाने की इजाजत न दे। 'विवाद से विश्वास' योजना से सरकार को एकबारगी कर राजस्व का पुलिंदा मिल सकता है। लेकिन महज एक बार होने वाले विनिवेश प्राप्तियों की तरह यह लाभ भी तब तक कायम नहीं रहेगा जब तक कराधान प्रणाली में टिकाऊ सुधार नहीं लागू किए जाते हैं और विवादों का जल्द समाधान नहीं तलाशा जाता है।

कानाफूसी

भाजपा की चिंता

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) की शानदार जीत ने दिल्ली सचिवालय पर काबिज होने का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का इंतजार तो लंबा किया ही है, उसने स्थानीय निकायों पर भाजपा के नियंत्रण को भी खतरा उत्पन्न कर दिया है। दिल्ली के तीनों स्थानीय निकायों पर भाजपा 13 वर्ष से काबिज है। अब चर्चा है कि दिल्ली सरकार सफाई पर ध्यान केंद्रित करने वाली है। इस क्षेत्र में निगमों की अहम भूमिका है और राज्य सरकार के अधिकार भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस जानकारी के बाद भाजपा के पार्षद असहज हो गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप अब निकाय चुनावों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में आप का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। दूसरी बात यह कि सरकार इन निकायों द्वारा किए गए कुछ कामों का श्रेय भी ले सकती है।

जीएसटी में इजाफा

ऐसे वक्त में जबकि बेरोजगारी बढ़ रही है, आय में कमी आ रही है और मांग और खपत घट रही हैं, किसी को भी लगता कि वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में कमी आएगी क्योंकि यह कर खपत आधारित है। परंतु चकित करने वाली बात यह है कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है। गत वर्ष दिसंबर में जीएसटी एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया था। जब एक जीएसटी अधिकारी से इस बदलते रुझान की वजह पूछी गई तो उन्होंने प्रतिप्रश्न दागते हुए कहा कि आप अपने कपड़े धोकर सुखाने के पहले क्या करते हैं? इसका उत्तर भी खुद ही देते हुए उन्होंने कहा कि उन कपड़ों को निचोड़ा जाता है। जाहिर है उनका इशारा कड़े कर वंचना नियमों की ओर था जिनकी मदद से सरकार अनुपालन सुनिश्चित करने में लगी है। हालांकि अधिकारी ने यह भी कहा कि ऐसे उपाय राजस्व में निरंतर वृद्धि की गारंटी नहीं हो सकते।

आपका पक्ष

किसानों की योजना पर भ्रष्टाचार का ग्रहण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान हित में है, क्योंकि इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन हो सकता है कि इस योजना का फायदा उन लोगों ने उठाया हो जिनके पास खेत तो है लेकिन वह उस पर खेती नहीं करते होंगे। इसके अलावा वे इतनी खेती नहीं करते होंगे, जिससे कि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों के खाते में इस योजना की राशि पहुंच रही होगी। ऐसे में इसकी निष्पक्ष और उचित जांच करने की जरूरत है। ऐसे लोग सत्ताधारी नेताओं अथवा इस योजना से संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से इस योजना का लाभ ले रहे होंगे जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। कृषि से देश को आर्थिक फायदा होना चाहिए जिससे देश का राजस्व बढ़ सके। यहां यह भी कहना उचित होगा कि किसानों

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ उचित किसानों को मिले

की खराब हालात के लिए शायद कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है। तभी जरूरतमंद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और उनका हक कोई और ले जाता है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में बैठकर जो योजनाएं किसानों के लिए बनाती हैं वे भ्रष्टाचार के कारण दूरदराज गांवों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

आपराधिक तत्त्वों का राजनीति में आना

राजनीति में अपराधी तत्त्वों का बढ़ना आज के समय में कोई नई बात नहीं रह गई है। यह राजनीति में एक सामान्य बात होती जा रही है। आज वह समय नहीं रह गया जब राजनीति को एक पवित्र और सेवा भाव का कार्य समझा जाता था। आजादी के समय देश के समस्त नेताओं ने गांधीजी के रामराज्य के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लिया था। लेकिन वर्तमान में भारतीय राजनीति में अपराधी तत्त्व जिस तेजी से आ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। इसे सुधारने के लिए सर्वप्रथम देश की चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है। राजनीति में धन व शक्ति का बोलबाला है। एक आकलन के अनुसार सामान्यत: 90 प्रतिशत से भी अधिक नेतागण धनाढ्य परिवारों से आते हैं। वहीं कुछ नेताओं का संबंध अपराधी तत्त्वों से होता है। गुणवत्ता कभी भी हमारी चुनाव प्रक्रिया का आधार नहीं रही है। किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला साबित हो और वह सजा पाए यह बहुत कम ही देखने को मिलता है। न्यायिक प्रक्रिया में काफी समय लगता है और तब तक अपराधी तत्त्व राजनीति में बने रहते हैं। इसलिए ऐसा कानून बने कि आपराधिक छवि वाले लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाया जाए। तभी राजनीति में अपराधी तत्त्वों पर कुछ हद तक अंकुश लग सकेगा। राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या पर अगर संसद भी रोक न लगा सकी तो अपराधियों को राजनीति से दूर रखने के लिए दो रास्ते बचते हैं। एक तो यह कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे। दूसरा देश की जनता ऐसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों का चयन न करे।

अनु मिश्रा, सीवान

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

एसईजेड पर नहीं काजू एमआईपी

भाषा
नई दिल्ली, 19 फरवरी

काजू गिरी पर लगाया गया न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) पर लागू नहीं होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक व्यापार नोटिस में यह जानकारी दी है। पिछले साल जून में डीजीएफटी ने साबुत और टूटी काजू गिरी पर एमआईपी एक झटके में ही बहुत ऊंचा कर दिया था। टूटी काजू गिरी का एमआईपी 288 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ा कर 680 रुपये तथा साबुत गिरी का एमआईपी 400 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ा कर 720 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया था। इस व्यवस्था के तहत इससे कम दर पर आयात नहीं किया जा सकता। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) या निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) में स्थापित इकाइयों पर एमआईपी के बारे में विदेश व्यापार विभाग के उप महानिदेशक गगनदीप सिंह ने कहा कि इस मामले में निदेशालय ने गौर किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों और सेज में स्थापित इकाइयों पर यह एमआईपी लागू नहीं होगा है। देश में एसईजेड और ईओयू को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इन क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों द्वारा आयातित कच्चे माल का उपयोग निर्यात उद्देश्यों के लिए किया जाता है। देश में लगभग 3.5 लाख टन काजू गिरी का उत्पादन होता है।

कच्चे काजू का उत्पादन और आयात क्रमश: आठ लाख टन और नौ लाख टन है। देश से अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, सऊदी अरब, जर्मनी, जापान, बेल्जियम, कोरिया, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, कुवैत, सिंगापुर, कतर, ग्रीस, इटली, ईरान और कनाडा सहित लगभग 80 देशों को काजू का निर्यात किया जाता है।

चीन के आर्थिक प्रोत्साहन से

जिंसों के संग सोने में भी तेजी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 19 फरवरी

जिंसों के दाम

धातु	डॉलर/टन	अंतर
तांबा	5785.5	0.4
जिंक	2146.0	0.1
निकल	12815.0	-0.3
एल्युमीनियम	1716.0	-0.3
सीसा	1881.0	-0.3
सोना (डॉलर/ओंस)	1610.0	0.5
चांदी (डॉलर/ओंस)	18.4	1.0
ब्रेंट क्रूड (डॉलर/बैरल)	58.2	1.5

अंतर पिछले कारोबार बंद होने से,
स्रोत- एलएमई, ब्लूमबर्ग

- चीन में आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाने की संभावना के बाद मांग में सुधार की उम्मीद जगी
- अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने लिए चीन 250 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था में डाल चुका है
- चीन को कोरोनावायरस से काफी नुकसान हुआ
- मुंबई के जवेरी बाजार में स्टैंडर्ड सोने के दाम सर्वकालिक शीर्ष स्तर 41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गए
- चांदी के दाम भी मजबूत होकर 47,600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए

मांग में सुधार की उम्मीद से कुछ चुनिंदा धातुओं, ऊर्जा और सराफा की कीमतों में बुधवार को 1.5 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। चीन में आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाए जाने की संभावना के बाद मांग में सुधार की उम्मीद जगी है। अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने लिए चीन पहले ही पिछले सप्ताह 250 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था में डाल चुका है। चीन को कोरोनावायरस के प्रकोप से काफी नुकसान हुआ है। जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 1.5 प्रतिशत तक उछलकर प्रति बैरल 58.20 डॉलर के स्तर पर पहुंच गए, वहीं दूसरी ओर लंदन के बेंचमार्क हाजिर बाजार में सोने और चांदी के दाम क्रमश: एक और 0.5 प्रतिशत तक बढ़कर 1,610 डॉलर प्रति औंस तथा 18.37 डॉलर प्रति औंस हो गए। मुंबई के जवेरी बाजार में स्टैंडर्ड सोने के दाम सर्वकालिक शीर्ष स्तर 41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गए। चांदी के दाम भी मजबूत होकर 47,600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए।

अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुए व्यापार युद्ध और इसके बाद पश्चिमी एशिया में राजीतिक अस्थिरता, ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से अलग होने (ब्रेक्जिट) और अब चीन में कोरोनावायरस की महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक विकास के सामने जोखिम की स्थिति पैदा हो गई है। इसके परिणामस्वरूप दुनिया की प्रमुख प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं ने पहले ही आर्थिक प्रोत्साहन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए जापान ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मंदी से बचाने के लिए 26 लाख करोड़ येन (239 अरब डॉलर) के पैकेज की घोषणा की है। विश्लेषकों का अनुमान है कि अब चीन, भारत और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस कदम का अनुसरण करेंगी।

आनंद राठी शेयर्स और स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड के निदेशक नवीन माथुर ने कहा कि चीन सरकार द्वारा नियोजित आर्थिक प्रोत्साहन की उम्मीद के कारण आज संवेदनशील जिंसों के दामों में तेजी आई है। इसके अलावा कोरोनोवायरस का प्रसार भी धीरे-धीरे कम हो रहा है जिससे आगे चलकर व्यापार धारणा में सुधार आने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि व्यापार का सकारात्मक परिदृश्य बन रहा है, लेकिन आर्थिक प्रोत्साहन मुद्रा के लिए नकारात्मक रहेंगे और इसी तरह सोने, ऊर्जा तथा कुछ मूल धातुओं के लिए सकारात्मक भी होंगे।

अलबत्ता बेंचमार्क लंदन मेटल एक्सचेंज पर निकल, सीसे और एल्युमीनियम जैसी गैर-निवेश से जुड़ी संवेदनशील जिंसों के दामों में कुछ गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर फरवरी में डिलिवरी वाले कच्चे तेल का वायदा भाव 1.78 प्रतिशत तक बढ़कर 3,764 रुपये प्रति बैरल हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार के दामों का अनुसरण करते हुए सोने और तांबे की कीमतें भी बढ़कर क्रमश: 41,580 रुपये प्रति 10 ग्राम और 431.90 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं।

कॉमट्रेंड्ज रिसर्च के निदेशक ज्ञानशेखर त्यागराजन ने कहा कि कोरोनावायरस महामारी अब भी मौजूद है। बाजार में कोरोनोवायरस जैसी घटनाओं से निपटने का अपना तरीका है। किसी भी घटना की त्वरित प्रतिक्रिया से बाजार ऊपर या नीचे चला जाता है। लेकिन फिलहाल बाजार की दिशा सोने जैसे सुरक्षित निवेश के पक्ष में है, जो निकट भविष्य में 1,625-1,645 डॉलर प्रति औंस के दायरे में रहेगा यानी स्थानीय मुद्रा के हिसाब से 42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम।

अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाले चीन के प्रोत्साहन के उपायों के बाद बुधवार को शांघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर मूल धातुओं के बंद भाव पर मिला-जुला असर रहा, हालांकि कोरोनोवायरस के प्रकोप को लेकर चिंता जारी है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एसोसिएट निदेशक किशोर नरणे ने कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन आने से वैश्विक स्तर पर गिरती ब्याज दरों में तेजी आएगी। इससे सोने जैसी सुरक्षित निवेश वाली परिसंपत्ति की ओर निवेश आकर्षित होगा। कोरोनावायरस के कारण स्मेल्टिंग क्षमता प्रभावित होने से चीन में काम बंद हुआ है। तांबे जैसी चुनिंदा धातुओं में तेजी आ सकती है।

विदेशी मांग से चढ़ेगा टमाटर!

सुशील मिश्र
मुंबई, 19 फरवरी

चीन, फ्रांस, स्पेन और इटली में फसल खराब होने के कारण टमाटर की बढ़े सकती है मांग

बाजार में नई फसल की आवक शुरू होते ही आलू, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों के दामों से लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। जनवरी से अब तक इनके दाम 50 से 60 फीसदी गिर चुके हैं। फिलहाल आलू और प्याज के दाम काबू में रहने की संभावना है, लेकिन टमाटर किसान इस बार मालामाल हो सकते हैं। चीन, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में फसल खराब होने के कारण टमाटर और उसके उत्पादों की विदेशी मांग बढ़ने की संभावना बन चुकी है जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ेगा।

जनवरी से अब तक टमाटर की कीमतें आधी हो गई हैं। साल की शुरुआत में थोक बाजार में टमाटर के दाम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल और खुदरा बाजार में 60 रुपये प्रति किलोग्राम पार कर चुके थे। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ) से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक साल की शुरुआत में दिल्ली के थोक बाजार में टमाटर की औसत कीमत 2,057 रुपये प्रति क्विंटल और मुंबई में 1,200 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो 15 फरवरी को गिरकर क्रमश: 941 रुपये और 700 रुपये हो गई। पिछले दो दिन में टमाटर के भाव में अचानक तेजी देखने को मिली है। मुंबई के थोक बाजार में टमाटर के दाम अचानक बढ़कर 1,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के कारोबारी आपूर्ति में कमी को इस कीमत वृद्धि की वजह बता रहे हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि दरअसल बाजार में एक बात तेजी से फैल रही है कि टमाटर की फसल खराब हो गई है। साथ ही टमाटर के उत्पाद बनाने वाली कंपनियां बड़ी मात्रा में किसानों से माल खरीद रही हैं जिस कारण कीमतों में अचानक तेजी देखी जा रही है।

टमाटर उत्पाद बनाने वाली कंपनियों द्वारा खरीदारी बढ़ाने की वजह चीन और यूरोप में मांग बढ़ने के आसार को माना जा रहा है। फ्रांस के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र फिनिस्टर में टमाटर के पौधे एक घातक विषाणु से संक्रमित हो गए हैं जिस कारण पूरी फसल नष्ट होने की आशंका है। फ्रांस के कृषि मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि संक्रमण का कोई उपचार नहीं है इसलिए एक खेत को पृथक कर दिया गया है और टमाटरों से भरे ग्रीनहाउस नष्ट कर दिए जाएंगे। टमाटर के पौधों में विषाणु से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। इससे टमाटर पर धब्बे पड़ जाते हैं और यह खाने लायक नहीं रहता है। इस विषाणु का मानवों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। पहली बार इसका पता 2014 में इजराइल में चला था। पिछले साल जुलाई में ब्रिटेन में इस विषाणु का पहला मामला सामने आया था। यूरोपीय संघ के देशों में टमाटर के सबसे बड़े उत्पादक देश स्पेन और इटली के किसानों के खेत भी इस विषाणु से प्रभावित हो चुके हैं। फ्रांस ने फरवरी की शुरुआत में पौधों और बीजों की जांच को प्राथमिकता दी थी।

भारत के टमाटर और टमाटर से निर्मित उत्पादों का निर्यात करने वाले कारोबारियों को उम्मीद है कि इसका फायदा भारतीय किसानों को मिलेगा। विदेशी मांग बढ़ने की पूरी उम्मीद है। यूरोपीय देशों से मांग बढ़ेगी। साथ ही जो देश स्पेन, इटली और फ्रांस से टमाटर और इसके उत्पाद आयात करते थे, वे भी दूसरे बाजारों की तरफ रुख करने के लिए मजबूर होंगे जिसका फायदा भारतीय कंपनियों और किसानों को मिलने की उम्मीद है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के मुताबिक भारत ने 2018-19 में 471 करोड़ रुपये का टमाटर और इसके उत्पादों का निर्यात किया था। एक अनुमान के मुताबिक इस बार यह निर्यात 800 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही घरेलू बाजार में भी कीमतों पर असर पड़ेगा यानी इस साल टमाटर के भाव तेजी से बढ़ सकते हैं।

सरकार टमाटर सहित दूसरी जरूरी सब्जियों के दाम काबू में रखने की तैयारी में पहले से जुटी हुई है। आने वाले समय में आलू, प्याज और टमाटर जैसी आवश्यक सब्जियों के दाम काबू में रखने के लिये सरकार ने एक कीमत स्थिरीकरण कोष बनाने का प्रस्ताव बजट में किया था। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज, आलू और टमाटर समेत तमाम जरूरी खाने-पीने के सामान के बफर स्टॉक से आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020 पेश करते हुए कहा था कि सरकार ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों की कीमतें नियंत्रण में रखने के लिये समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार दलहन, प्याज और आलू जैसी आवश्यक कृषि-बागवानी जिंसों की कीमतों में उथल-पुथल रोकने के लिये पीएसएफ लागू करने की योजना बना रही है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Feb 19	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,681.0	-3.1	1,970.4	4.7
Copper	5,728.0	-1.6	6,302.4	2.7
Nickel	12,880.0	-11.0	13,624.9	-13.1
Lead	1,901.0	-3.4	2,082.2	-2.4
Tin	16,520.0	3.4	17,677.5	3.9
Zinc	2,128.0	-9.9	2,403.6	-11.1
Gold ($/ounce)	1,608.4*	9.2	1,802.4	9.2
Silver ($/ounce)	18.3*	6.8	20.7	6.7
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	58.1*	-4.7	55.8	-10.3
Natural Gas ($/mmBtu)	2.0*	-21.9	2.0	-22.1
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	196.2	5.8	290.0	-3.5
Maize	182.8*	1.1	247.2	-4.1
Sugar	421.9*	25.6	485.5	-0.4
Palm oil	675.0	6.3	1,077.8	6.8
Rubber	1,470.5*	-1.5	1,900.5	5.7
Coffee Robusta	1,261.0*	-3.2	1,802.7	-3.9
Cotton	1,506.9	7.7	1,575.0	0.7

* As on Feb 19, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.6& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	77.6	41029
Oil and Oilseeds	246.8	90783
Spices	0.3	10
Metal(Feb 18)		
Metal- non ferrous	5413.6	55913
Metal- precious	13262.4	392
Oil and gas(Feb 18)		
Gas	3099.9	42455
Oil	17643.4	2206

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	122.3	135161
Grains	111.1	88260
Oil and Oilseeds	527.9	405650
Others	84.8	61695
Pulses	90.1	42740
Spices	77.1	21247

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Silver (Mar 05)	47263.0	2.5
Silver Mini (Feb 28)	47273.0	2.5
Silver Micro (Feb 28)	47273.0	2.4
Natural Gas (Feb 25)	141.5	1.7
Gold (Apr 03)	41420.0	1.6
Gold Mini (Mar 05)	41311.0	1.5
Losers (* % Change)		
Nickel (Feb 28)	938.2	-1.7
Crude Oil (Feb 19)	3698.0	-1.0
Copper (Feb 28)	431.6	-0.9
Crude Palm Oil (Feb 28)	705.3	-0.6
Mentha Oil (Feb 28)	1154.5	-0.6
Cotton (Feb 28)	19160.0	-0.4

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Losers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6198.0	3.8
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1700.0	1.1
Soyabean Indore (Feb 20)	4000.0	0.7
Barley Jaipur (Apr 20)	1680.0	0.6
Coriander-Kota (Apr 20)	6161.0	0.6
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3900.0	0.4
Losers (* % Change)		
Maize IndusNizamabad (May 20)	1655.0	-2.9
Chana-Bikaner (Mar 20)	4023.0	-0.8
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	822.2	-0.2
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1042.0	-0.1
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	3950.0	-0.1
Jeera Unjha (Mar 20)	13690.0	0.0

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Apr 30)	1043.5	3.8
Cotton-Rajkot (Feb 28)	19160.0	1.2
Zinc Mumbai (May 29)	172.3	0.6
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Feb 28)	1154.5	-11.1
Cardamom Vandanmedu (Mar 13)	3158.1	-10.2
Lead Min Mumbai (Feb 28)	146.6	-4.6
Lead Mum (May 29)	148.0	-3.7
Gold Petal-Mumbai (Feb 28)	4056.0	-2.4
Nickel Mumbai (Feb 28)	938.2	-2.4
Zinc Mini Mumbai (Feb 28)	167.7	-2.1
Aluminium Mum (May 29)	136.8	-1.7
Copper Mum (Feb 28)	431.6	-1.4

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6198.0	6.1
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3051.0	1.7
Maize-Sangli (Feb 20)	1769.0	1.1
Crude Palm Oil Kandl (Feb 28)	713.4	1.0
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1745.0	0.9
Moong-Merta City (Feb 20)	7759.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1680.0	-20.1
Jeera Unjha (Mar 20)	13690.0	-3.3
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	6612.0	-1.2
Soy Bean Indore (Feb 20)	4000.0	-0.8
29 mm Cotton-Rajkot (Feb 20)	18790.0	-0.2

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	..............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	105......(105)
Aluminium ingots /kg	141......(141)
Brass sheet cutting /kg	325......(325)
Brass utensil scraps/kg	308......(308)
Copper heavy scrap /kg	418......(418)
Copper utensil scraps/kg	393......(393)
Copper wire bar /kg	451......(451)
Lead ingots /kg	149......(149)
Nickel Cathodes /kg	975......(975)
Tin slabs /kg	1265......(1265)
Zinc slabs /kg	172......(172)
Source:Bombay Metal Exchange	
Cotton	..............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10011......(10011)
DCH - 32 /Qtl	11332......(11304)
Jaydhar /Qtl	9758......(9758)
Shankar- 6 /Qtl	11079......(11051)
Source:Cotton Association of India	
Oil	..............Mumbai
Castor FSG /10kg	848......(845)
Castor Comm /10kg	838......(835)
Ricebran oil/10kg	820......(820)
Groundnut oil /10kg	1130......(1130)
Linseed oil /10kg	880......(890)
Karanji /10kg	800......(800)
Palm oil /10kg	785......(790)
Sunflower exp ref /10kg	870......(870)
Sunflower oil exp /10kg	805......(805)
Soyabean ref / 10kg	820......(822)
Source:Bombay Commodity Exchange	

सॉफ्ट

Sugar	..............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3352-3596 ......(3352-3596)
Source:Bombay Sugar Merchants Association	

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	....
NYSE Crude	52.71......(52.05)
Brent Crude (UK)	58.15......(57.3)
Brent Crude (WTI)	52.05......(52.05)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.97......(1.98)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	308.2......(298.73)
Naptha spot /Rs/MT	45170......(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150......(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950......(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com	

सर्राफा

Gold	..............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	41469......(40970)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	41636......(41135)
Silver.999/ kg	47700......(46545)
Source:India Bullion & Jewellers Association	

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18777.40	18835.15
Alumini-Mumbai (M)	1 K	139.50	139.10
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1742.50	1742.50
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1744.10	1730.20
Barley Jaipur (N)	1 Q	2109.35	2102.80
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3567.00	3525.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4034.50	4024.35
Castor Seed-Kadi (N)	X	4010.00	4022.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4103.75	4063.10
Chana Delhi (N)	1 Q	4316.50	4270.30
Chana-Akola (N)	X	4075.00	4075.00
Coriander-Gondal (N)	X	6111.00	6133.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6182.50	6133.75
Coriander-Kota (N)	1 Q	6222.10	6172.45
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1783.25	1786.55
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1828.40	1823.85
Cotton-Kadi (N)	1 B	18883.60	18883.60
CPO-Kandla (M)	10 K	710.80	700.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	712.25	706.20
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	700.00	685.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	902.15	899.90
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1551.20	1548.40
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3456.70	3456.70
Gold Ahm (M)	10 G	40976.00	41491.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32913.00	33326.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4109.00	4157.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	6675.35	6694.25
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3782.50	3819.25
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3775.00	3725.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1111.70	1114.25
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	102.45	102.35
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	14850.00	14700.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	14237.50	14157.15
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	810.55	814.70
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1006.10	998.15
Kapas-Rajkot (N)	X	991.00	997.20
Lead Mum (M)	1 K	151.40	153.65
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1800.00	1800.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	1965.00	1897.25
Maize-Erode (N)	X	1876.00	1887.80
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	1965.00	1897.25
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	1875.00	1862.50
Maize-Sangli (N)	X	1767.70	1750.00
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4775.00	4743.75
Moong-Merta City (N)	1 Q	7756.25	7741.65
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4231.00	4231.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	965.70	961.40
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3050.00	3000.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3106.00	3111.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	337.60	339.60
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33875.00	34000.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	815.00	815.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	780.00	773.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1909.05	1923.25
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5300.00	5266.65
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	780.00	771.25
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	825.95	825.00
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	829.95	826.85
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	836.25	836.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13650.00	13600.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13608.00	13600.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46433.00	47650.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4008.00	4033.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	3913.75	3932.15
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4105.65	4115.75
Soy Bean-Akola (N)	X	4045.00	4045.00
Soymeal Indore (N)	1 T	32250.00	32100.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	825.80	824.60
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	31320.00	30890.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31760.00	31490.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28860.00	28440.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3155.00	3205.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3380.95	3375.00
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3258.50	3258.50
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3400.00	3395.25
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3260.85	3262.05
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3132.50	3132.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5775.00	5842.85
Wheat Delhi (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2158.20	2171.80
Wheat New Indore (N)	1 Q	2168.15	2195.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2100.00	2085.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2200.00	2190.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	6500.00	6500.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5950.00	5800.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	171.00	171.25

* as on Feb 18, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION
दिवस सत्र (बुधवार)
कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19200, 19200, 19150, 19160	3444	250	19681
Mar 31	19470, 19470, 19420, 19440	3057	182	17228
Apr 30	19710, 19720, 19680, 19710	174	20	2895
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1692, 1711, 1667, 1700	1470	63	10790
Mar 20	1703, 1727, 1681, 1690	48270	3531	86610
Apr 20	1721, 1749, 1703, 1715	11680	956	24920
May 20	1745, 1774, 1729, 1745	1960	177	8510
Jun 19	1805, 1805, 1805, 1805	100	8	900
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1043, 1046, 1041.5, 1043.5	344	69	1208
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1052, 1052, 1041, 1042	659	329	3431
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1678, 1680, 1670, 1680	130	11	2520
May 20	1705, 1705, 1680, 1680	60	6	2790
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	-, 3774, -, 3774	25	1	90
Mar 20	3818, 3850, 3806, 3826	22620	2308	69465
Apr 20	3850, 3882, 3848, 3858	6150	537	13085
Maize IndusNizamabad NCDEX(1 Q)				
May 20	1654, 1655, 1654, 1655	170	3	310
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3900, 3900, 3890, 3900	340	21	735
Mar 20	3950, 3950, 3906, 3922	3385	395	21770
Apr 20	3966, 3970, 3938, 3946	865	111	8510
May 20	3980, 3980, 3954, 3962	150	16	620
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	713, 717, 704.6, 705.3	13970	980	34650
Mar 31	707.1, 710.4, 698.4, 699	16330	963	42950
Apr 30	703.5, 709, 697.6, 698.3	1500	119	12840
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1162.9, 1166, 1150.4, 1154.5	97.2	218	169.2
Mar 31	1153, 1155.2, 1145.2, 1147.7	91.44	160	158.04
May 29	1111.3, 1111.3, 1093.4, 1099.4	1.08	3	5.4
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	3933, 3950, 3933, 3950	50	5	240
Apr 20	4002, 4029, 3997, 4002	14140	1109	17270
May 20	4038, 4058, 4035, 4046	1370	135	4130
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	822, 825.6, 820.8, 822.2	2930	163	7480
Mar 20	810.8, 815, 807.8, 808.6	21050	2153	51035
Apr 20	804.2, 811.8, 803.6, 806.2	6680	673	12315
May 20	806.2, 806.2, 803.4, 803.8	55	11	215
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4000, 4010, 3970, 4000	600	68	2360
Mar 20	3834, 3930, 3834, 3864	25770	3188	138815
Apr 20	3874, 3902, 3836, 3840	16575	2031	108375
May 20	3876, 3914, 3850, 3856	6450	606	30270
Jun 19	3904, 3946, 3898, 3932	1445	199	1500
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	-, 6612, -, 6612	10	2	100
Mar 20	6601, 6678, 6590, 6635	9670	1426	51200
Apr 20	6692, 6760, 6677, 6714	3060	314	10385
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	4035, 4055, 4012, 4023	13960	1205	16460
Apr 20	3960, 3998, 3960, 3973	7870	688	20450
May 20	4000, 4029, 4000, 4021	650	65	4620
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Mar 13	3174.9, 3199, 3130, 3158.1	0.6	6	7.2
Apr 15	3220, 3250, 3220, 3236.7	0.3	3	2.6
May 15	3300, 3300, 3300, 3300	0.1	1	0.2
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6081, 6175, 6062, 6161	5550	458	7090
May 20	6120, 6149, 6100, 6123	260	26	980
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	13700, 13785, 13600, 13690	771	202	2028
Apr 20	13500, 13555, 13440, 13500	216	65	1824
May 20	13560, 13575, 13555, 13575	18	6	135
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	5970, 6210, 5970, 6198	2580	421	3770
Apr 20	6000, 6194, 5972, 6164	1845	328	5220
May 20	6090, 6216, 6090, 6214	120	20	200
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	138.15, 138.65, 137.65, 137.8	4861	3110	4916
Mar 31	137.9, 138.25, 137.7, 137.9	1076	654	1862
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	432, 433.95, 431.3, 431.65	15772.5	5318	11987.5
Mar 31	436.5, 437.75, 435.6, 435.9	1887.5	648	2750
Apr 30	438, 438.7, 438, 438.35	5	2	5
Lead MCX(1 K)				
May 29	148, 148, 148, 148	1	1	8
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	146.65, 147.05, 146.1, 146.25	6561	4251	5607
Mar 31	147.15, 147.65, 146.9, 147.05	557	485	1735
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	947, 950.2, 939.4, 941.1	9373.5	5530	3676.5
Mar 31	944.9, 946, 937.2, 939.2	444	283	768
Zinc MCX(1 K)				
May 29	171.9, 171.9, 171.9, 171.9	3	2	17
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	167.9, 168.45, 167.4, 167.75	21694	12390	23491
Mar 31	169.25, 169.85, 169.1, 169.5	2772	1829	9263
Apr 30	170.35, 170.4, 169.75, 169.95	471	324	657
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	41408, 41619, 41350, 41593	7.5	6346	17.72
Jun 05	41583, 41781, 41537, 41755	0.21	192	6.84
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32628, 32730, 32605, 32688	0	255	0.01
Mar 31	32730, 32832, 32640, 32798	0	194	0.01
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	41400, 41478, 41230, 41456	0.91	7628	1.03
Apr 03	41392, 41569, 41313, 41549	0.26	2157	0.63
May 05	41450, 41650, 41417, 41629	0.01	71	0.04

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	4055, 4065, 4049, 4064	0	682	0.01
Mar 31	4090, 4096, 4077, 4094	0	498	0.01
Apr 30	4096, 4130, 4093, 4101	0	36	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	47381, 47710, 47285, 47645	372.81	9863	273.06
May 05	47937, 48210, 47800, 48178	18.48	540	69.39
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	47101, 47700, 47060, 47639	36.47	25173	23.2
Apr 30	47800, 48219, 47800, 48177	7.79	5214	10.49
Jun 30	48235, 48560, 48061, 48537	0.06	58	0.37
Aug 31	47181, 48550, 47181, 47866	0	2	0.02
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	47350, 47709, 47292, 47647	96.03	15349	50.24
Apr 30	47880, 48220, 47804, 48182	10.98	1908	11.85
Jun 30	47444, 48300, 47444, 48028	0.03	5	0.06
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	141, 141.5, 139.9, 140.7	51284mb	23721	35671mb
Mar 26	141.1, 141.6, 140.3, 141.1	5610mb	2928	12850mb
Apr 27	144.1, 144.9, 143.8, 144.6	233mb	162	1375mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3710, 3770, 3710, 3764	10526bl	56313	2086bl
Mar 19	3745, 3809, 3745, 3799	2675bl	18118	1553bl
Apr 20	3800, 3836, 3800, 3827	40bl	320	28bl

सायं सत्र (मंगलवार)
कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19200, 19270, 19100, 19170	8176	1088	22321
Mar 31	19450, 19550, 19410, 19430	6769	839	14728
Apr 30	19720, 19810, 19680, 19750	1114	169	2857
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1047.5, 1047.5, 1040.5, 1042.5	1540	211	1112
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1043, 1049.5, 1039, 1043	1306	694	3388
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	712, 716.5, 706.6, 715.8	18700	1519	35360
Mar 31	704.6, 711, 699, 709.8	21700	1445	40140
Apr 30	699.5, 709.5, 696.9, 708.2	2420	135	12540
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	830, 831.6, 823, 824.2	4745	319	8085
Mar 20	810.4, 813.6, 802, 812.8	33215	3384	52255
Apr 20	797.6, 808.4, 796.4, 807.6	6875	844	11890
May 20	796.8, 802.2, 793.8, 796.2	145	16	200
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	137.9, 138.4, 137.65, 138.05	10731	6474	4297
Mar 31	138.6, 138.7, 137.35, 137.6	1340	927	1437
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	434.2, 434.35, 430.55, 431.6	31775	10665	11062.5
Mar 31	437.1, 437.35, 434.45, 435.7	1772.5	646	2287.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	145.6, 147.1, 144.7, 146.6	17354	10951	4415
Mar 31	146.65, 147.6, 145.7, 147.1	1257	869	1637
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	947, 950.5, 935.5, 938.2	26808	15935	2524.5
Mar 31	949.1, 951.9, 936.6, 939.9	963	585	604.5
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	167.9, 168.2, 166.65, 167.65	49881	27203	19306
Mar 31	169.5, 169.85, 168.5, 169.3	3749	2346	8067
Apr 30	170.35, 170.35, 169.2, 169.6	241	148	244
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40900, 41480, 40900, 41420	14.83	12619	16.77
Jun 05	41125, 41630, 41070, 41587	0.61	465	6.71
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32503, 32744, 32401, 32646	0.01	494	0.01
Mar 31	32450, 32788, 32450, 32742	0.01	426	0.01
Apr 30	32509, 32812, 32346, 32689	0	17	0
May 29	32850, 32850, 32850, 32850	0	1	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	40820, 41343, 40800, 41311	2.23	18379	0.89
Apr 03	40900, 41435, 40880, 41391	0.55	4450	0.54
May 05	41080, 41524, 40954, 41482	0.04	296	0.04
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	4026, 4060, 4025, 4056	0.01	1496	0.01
Mar 31	4049, 4089, 4047, 4085	0	1306	0.01
Apr 30	4055, 4098, 4053, 4092	0	40	0
May 29	4093, 4093, 4093, 4093	0	2	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46450, 47330, 46282, 47263	825.72	22997	229.32
May 05	46950, 47799, 46791, 47748	27.87	808	64.35
Jul 03	47028, 48999, 47028, 48014	0.06	2	0.03
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46270, 47328, 46270, 47273	93.68	63836	18.06
Apr 30	46840, 47801, 46830, 47766	14.34	10081	9.34
Jun 30	47303, 48177, 47300, 48144	0.1	89	0.33
Aug 31	48000, 48434, 48000, 48260	0.01	2	0.02
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46299, 47335, 46299, 47273	245.45	38780	34.88
Apr 30	46998, 47800, 46825, 47765	18.79	3148	10.23
Jun 30	47792, 47792, 47792, 47792	0.01	1	0.06
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	138.5, 141.9, 137.8, 141.5	208085mb	89658	30440mb
Mar 26	139, 141.9, 138.6, 141.6	12925mb	7517	10663mb
Apr 27	142.3, 145, 142.3, 144.8	691mb	489	1353mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3721, 3721, 3634, 3698	42897bl	220119	1204bl
Mar 19	3760, 3760, 3675, 3738	5062bl	37674	983bl
Apr 20	3750, 3770, 3707, 3768	42bl	356	20bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

दवा निर्यात पर रोक की सिफारिश

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उप सचिव ने विदेश व्यापार महानिदेशालय को लिखा पत्र

एजेंसियां

देश में दवाओं की किल्लत पैदा होने की आशंका को देखते हुए एक सरकारी समिति ने 12 ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएंट्स (एपीआई) और दवाओं के निर्यात पर रोक लगाने की सिफारिश की है। चीन में कोरोनावायरस फैलने के कारण वहां से दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल नहीं आ पा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग के लिए दवा बनाने में अड़चन पैदा हो गई है।

चीन से कच्चे माल की आपूर्ति पर नजर रखने के लिए गठित एक सरकारी समिति ने 12 एपीआई और दवाओं के निर्यात पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इन एपीआई और दवाओं में सामान्य एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स शामिल हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को भेजे एक पत्र में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उप सचिव एम के भारद्वाज ने 12 एपीआई और दवाओं के निर्यात पर रोक लगाने को कहा है। डीजीएफटी निर्यात से संबंधित मामलों को देखता है। इन 12 एपीआई और दवाओं में प्रोजेस्टेरोन के अलावा क्लोरमफेनिकोल, नियोमाइसीन, मेट्रोनाइडिजोल जैसी एंटीबायोटिक और विटामिन बी1, बी12, बी6 आदि शामिल हैं।

चीन से कच्चे माल की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता से देश के घरेलू बाजार बाजार में अड़चनें पैदा होने लगी हैं। छोटी दवा कंपनियां बड़ी मात्रा में कच्चे माल का स्टॉक नहीं रखती हैं ताकि उन्हें कम कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़े। इन छोटी दवा कंपनियों का कहना है कि अब उनके पास केवल करीब 15 से 20 दिन का ही कच्चा माल बचा है।

ठेके पर दवा बनाने वाली कंपनियों का भी कहना है कि पिछले एक पखवाड़े के दौरान ऑर्डरों में भारी कमी आई है। इसकी वजह यह है कि बड़ी दवा कंपनियां कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण फिलहाल ऑर्डर देने से बच रही हैं। इसके अलावा इस उद्योग के आंकड़े दर्शाते हैं कि पूरे उद्योग में दवा का स्टॉक भी बहुत अधिक नहीं है।

सरकारी समिति ने 12 एपीआई व दवाओं के निर्यात पर रोक की सिफारिश की

दवा	20 जन. को स्टॉक (दिन में)
एंटी-इन्फेक्टिव	43
एमोक्सिसिलीन+क्लावयूलैनिक एसिड	39
सेफट्रायएक्जोन	51
ऐंटी-डायबिटीक	31
ग्लीमेपिराइड+मेटफोरमिन	32
वोगलिबोस +मेटफोरमिन+ ग्लीमेपिराइड	33
ह्यूमन प्रीमिक्स इंसुलिन	29
पैरासिटामोल	52

स्रोत : एआईओसीडी एडब्ल्यूएसीएस

गुजरात की एक छोटी सूचीबद्ध कंपनी लिंकन फार्मास्यूटिकल्स के प्रबंध निदेशक (एमडी) महेंद्र पटेल ने कहा कि ज्यादा दवा विनिर्माता कंपनियों के पास कच्चे माल का स्टॉक करीब 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। पटेल ने कहा कि पैरासीटामोल जैसी कुछ अहम दवाओं के ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडीएंट्स (एपीआई) भारत में बनते हैं, लेकिन एपीआई बनाने की प्रक्रिया मे इस्तेमाल होने वाली प्रमुख शुरुआती सामग्री (केएसएम) या मध्यवर्ती तत्वों का आयात चीन से होता है।

पटेल ने दावा किया, 'चीन से आपूर्ति में अवरोध पैदा होने से पैरासीटामोल की मध्यवर्ती सामग्री की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों में करीब 70 फीसदी बढ़ गई हैं। इसके अलावा चीन में हालात सामान्य होने पर भी वहां के वेंडरों की आपूर्ति नियमित होने में कम से कम एक महीना लगेगा। इसके चलते निश्चित रूप से घरेलू बाजार में व्यवधान पैदा होगा।'

ठेके पर दवा बनाने वाली कंपनियां भी इस बात से सहमत हैं। उनके ऑर्डरों में पहली ही गिरावट आ चुकी है, लेकिन अब बड़ी कंपनियां ऑर्डर देने से पहले इंतजार कर रही हैं। मुंबई की ठेक पर दवा बनाने वाली एक बड़ी कंपनी ने कहा कि उसके ऑर्डर फरवरी में कम से कम 10 से 15 फीसदी घट चुके हैं। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम कच्चे माल का स्टॉक नहीं करते हैं। जब हमें ऑर्डर मिलता है तो हम उस समय की बाजार कीमतें देखते हैं और उसी के मुताबिक कीमतें बताते हैं। हम आम तौर पर ऑर्डर की डिलिवरी 45 दिन में करते हैं। पिछले कुछ दिनों में अहम एपीआई और अन्य मध्यवर्ती सामग्री की कीमतें बढ़ने से दवा कंपनियां ऑर्डर देने में थोड़ी झिझक रही हैं।'उन्होंने कहा कि दवा कंपनियां इतनी ऊंची कीमतों पर कच्चा माल खरीदने से पहले दवाओं के स्टॉक और कच्चे माल के स्टॉक को खत्म करेंगी। उन्होंने कहा, 'दवाओं की खुदरा कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं, इसलिए कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ विनिर्माताओं को ही वहन करना होगा।' हालांकि बड़ी दवा कंपनियों ने कहा कि यह सही है कि दवा कंपनियां ऊंची कीमतों पर कच्चा माल खरीदने के लिए आगे नहीं आएंगी, लेकिन वे अपने ग्राहक भी नहीं गंवा सकती हैं।

देश की एक शीर्ष दवा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमने अभी खतरे की घंटी नहीं बजाई है। बाजार में भी अभी दवा की कोई कमी नहीं है। लेकिन यह सही है कि स्टॉक खत्म होता जा रहा है। अभी हमें अगले दो महीनों में प्रमुख दवाओं की किल्लत पैदा होने की आशंका नजर नहीं आ रही है।' दवा उद्योग के लॉबी समूहों ने कहा कि उनके सदस्यों (ज्यादातर बड़ी कंपनियां) के पास डेढ़ महीने का और कच्चा माल है। इसमें दवा आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद दवाओं को शामिल करते हैं तो यह कम से कम दो महीने के लिए काफी है। हालांकि इस समय आपूर्ति श्रृंखला में स्टॉक बहुत अधिक नहीं है क्योंकि बिकने वाले स्टॉक की आपूर्ति की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

कोरोना: चीन से आयात पर मंडरा रहा खतरा

पुनीत वाधवा

चीन में फैली कोरोनावायरस की महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार जूझ रहे हैं ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि भारत लंबी अवधि में फायदा पाने में कारगर हो सकता है क्योंकि कंपनियां चीन के मुकाबले वैकल्पिक विनिर्माण आधार तैयार करने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं। हालांकि लघु अवधि में देश की कंपनियों को आपूर्ति बाधा का संकट झेलना होगा।

सीएलएसए के विश्लेषकों ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 में चीन से भारतीय आयात 70.4 अरब डॉलर रहा। चीन पर आयात निर्भरता ज्यादा होने की वजह से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि देश की दवा, रसायन, बिजली कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला में बाधा वाली स्थिति से जूझना पड़ सकता है क्योंकि चीन की उत्पादन गतिविधियों में अभी लंबे समय तक गतिरोध रहने की आशंका है। सीएलएसए में वैश्विक प्रमुख (शोध) शॉन कोचरन ने कंपनी के विश्लेषक विकास कुमार जैन के साथ एक नोट लिखा है जिनमें उन्होंने कहा कि धातु, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तेल कंपनियों को कम वैश्विक मांग का सामना करना पड़ सकता है जिससे जिंसों की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

वित्त वर्ष 2019 में 70.4 अरब डॉलर का आयात

श्रेणी	फीसदी
गैर-इलेक्ट्रिकल मशीनरी	11
दूरसंचार उपकरण	11
इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे	8
कंप्यूटर हार्डवेयर	6
इलेक्ट्रिकल मशीनरी	5
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	3
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स	3
ट्रांसपोर्ट उपकरण	2
लौह एवं अलौह धातु उत्पाद	6
जैव रसायन	5
रसायनिक सामग्री	5
कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक की वस्तुएं	4
औषधीय एवं दवा उत्पाद	4
उर्वरक	3
धागे, फैब्रिक	3
अन्य	21

स्रोतः सीएलएसए रिपोर्ट

आपूर्ति में बाधा

सीएलएसए का कहना है कि अगर कोरोनावायरस का संकट अगले कुछ महीने में कम नहीं होता है तब डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, हैवेल्स इंडिया, वोल्टास और सिप्ला कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जिन्हें अगले कुछ महीने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वैश्विक आपूर्ति चीन के बजाय दूसरे देशों से होगी तब देश में परिधान और कपड़ा निर्यातकों को फायदा मिल सकता है और उन्हें लघु अवधि में ज्यादा ऑर्डर मिल सकता है।

सीएलएसए के नोट में कहा गया है, 'टेलीविजन पैनल, एलईडी चिप, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और मोटर्स के लिए कंप्रेसर के लिए देश की इलेक्ट्रॉनिक और व्हाइट गुड्स के निर्माताओं की ज्यादा निर्भरता चीन की आपूर्ति पर है। देश के ब्रांडों के लिए जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में बाधा जैसी स्थिति है। इन उत्पादों की कीमतों में 5-10 फीसदी तक की बढ़ोतरी है और इसमें आगे भी बढ़ोतरी हो सकती है अगर आपूर्ति की बाधा और लंबे समय तक बरकरार हती है।'

इसी वजह से ज्यादातर विश्लेषकों ने वर्ष 2020 के लिए वैश्विक वृद्धि (जीडीपी) अनुमान में कटौती करनी शुरू कर दी है। यूबीएस के मुताबिक वैश्विक जीडीपी जनवरी 2020 की तिमाही में 0.7 फीसदी के स्तर पर रह सकता है जो दिसंबर 2019 की तिमाही में 3.2 फीसदी तक था। हालांकि यूबीएस को उम्मीद है कि अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में तेजी आएगी और कोरोनावायरस से बड़ी संकटपूर्ण स्थिति का असर कम रहेगा तथा 2020 की जीडीपी वृद्धि 20 आधार अंक की कमी के साथ 2.9 फीसदी के स्तर पर रहने के आसार हैं। हालांकि सीएलएसए का मानना है कि घरेलू उपभोग में कमी से शेयर बाजार पर कोरोनावायरस का असर पड़ने की संभावना कम है लेकिन चीन की आपूर्ति श्रृंखला में गतिरोध और वैश्विक मांग में मंदी का डर सता रहा है। सीएलएसए के मुताबिक अगर वायरस का असर बढ़ता है तब भारतीय शेयरों का प्रदर्शन अच्छा होगा।

सीएलएसए ने अपने नोट में कहा है, 'अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लंबी अवधि में कोई असर दिखता है तब भारत को फायदा पहुंच सकता है क्योंकि यहां के बाजार पर कम असर पड़ा है। शेयर बाजार का कुछ हिस्सा वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और चीन से आपूर्ति श्रृंखला जुड़ी हुई है ऐसे में चिंताजनक स्थिति बन सकती है।'

जापान में यात्रियों को राहत

कोरोनावायरस की जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने के बाद जापान में तट के पास करीब दो हफ्ते से अधिक वक्त तक अलग रखे गए क्रूज पोत के सैकड़ों यात्रियों को जहाज से बाहर निकलने की इजाजत मिल गई और इन यात्रियों ने बुधवार को जहाज को अलविदा कहा।

चीन से बाहर कोरोनावायरस के संक्रमण पर नियंत्रण बनाए रखने के जापान के तरीके की काफी आलोचना होने लगी। जब डायमंड प्रिंसेस नाम के इस जहाज पर नकारात्मक रिपोर्ट वाले लोग सूटकेस लेकर बाहर निकलने के लिए कतार में खड़े थे उस वक्त भी संक्रमण के 79 मामले की घोषणा की गई थी। इस तरह जहाज पर सवार 620 से अधिक लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई।

चीन में भी कोरोनावायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बुधवार को 2,000 के पार हो गई हालांकि संक्रमण के नए मामले में दूसरे दिन भी कमी देखी गई जो जनवरी के मुकाबले सबसे कम था। ऐसी खबरों की वजह से एशियाई शेयरों और अमेरिका के वायदा शेयरों में भी बढ़त दिखी। हालांकि चीन वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि 29 जनवरी के बाद सबसे कम मामले सामने आए हैं जिसने 1,749 नए मामले की पुष्टि की थी।

आयोग ने कहा कि जिन 136 लोगों की जान गई उनमें से 132 हुबेई में मरें हैं। आयोग ने बताया कि इसके 1,185 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक आयोग ने बताया कि 11,977 मरीजों की हालत गंभीर बनी है और 5,248 लोगों के इससे पीड़ित होने की आशंका है। आयोग ने कहा कि अभी तक कुल 14,376 संक्रमित लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है।

एजेंसियां

जापान में मौजूद जहाज यात्री उड़ान भरने की तैयारी में

पेज 1 का शेष

आपूर्ति में बाधा से सैमसंग के लिए बेहतर हालात

आईडीसी में शोध निदेशक नवकेंद्र सिंह के अनुसार सैमसंग पर कारोनावायरस के संकट का काफी कम असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने कहा, 'सैमसंग का परिचालन सभी महाद्वीपों में फैला है और उसके पास काफी इन्वेंट्री भी है। वह चीन या भारत पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं है। ऐसे में चीन से आपूर्ति बाधित होने की वजह से पहली तिमाही में सैमसंग को मदद मिल सकती है।' सैमसंग इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम न केवल अपने अधिकांश पुर्जों का उत्पादन भारत में करते हैं बल्कि वियतनाम में हमारा बहुत बड़ा संयंत्र भी है। ऐसे में कोरोना संकट के कारण हमारे परिचालन पर खास असर पड़ने की आशंका नहीं है।' उन्होंने बताया कि कंपनी अपने दो नए प्रमुख मॉडल सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप और सैमसंग गैलेक्सी एस20प्लस मार्च तक बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। अभी इसकी प्री-बुकिंग चल रही है। पिछले साल सैमसंग की बाजार हिस्सेदारी में लगातार कमी आ रही थी।

कंपनियों की सीमा शुल्क में कटौती की मांग

अर्णव दत्ता

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद श्रेणी में कीमतें बढ़ने की आशंका के बीच इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों ने सरकार से सीमा शुल्क दरों में कटौती करने की गुहार लगाई है ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें संतुलित रहें। 1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट में दरों में बढ़ोतरी के कुछ हफ्ते बाद ही कंपनियों ने यह मांग करनी शुरू कर दी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेज और हैंडसेट कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई औद्योगिक संस्थाओं मसलन एमएआईटी, इंडियन सेल्युलर ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चर्सस एसोसिएशन (सीईएएमए) ने सरकार से संपर्क कर शुल्क दर में संशोधन करने की मांग की है। चीन से होने वाली कलपुर्जों की आपूर्ति में भारी कमी की स्थिति है ऐसे में ये संगठन इन सामग्री पर लगे ज्यादा शुल्क को वापस लेने की मांग कर रहे हैं ताकि उत्पादन लागत में किसी भी बढ़ोतरी को कम किया जा सके।

बजट के दौरान वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि मोबाइल हैंडसेट, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए जरूरी सामग्री की शुल्क दरों में बदलाव की घोषणा की थी। मोबाइल के प्रमुख हिस्से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, डिस्प्ले असेंबली और टच पैनल पर सीमा शुल्क की दरों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी जबकि एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कूलर में इस्तेमाल होने वाले कंप्रेसर और छोटे मोटर में 2.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई। हालांकि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला नहीं होने की वजह से इन वस्तुओं का आयात किया जाता है और ये आयात ज्यादातर चीन से किया जाता है। वाणिज्य विभाग के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2018-19 के दौरान 50,500 करोड़ रुपये तक के मोबाइल पुर्जे का आयात चीन से किया गया जबकि 4,000 करोड़ रुपये तक के एसी और एसी के कलपुर्जे चीन से आयात किए गए। सीईएएमए के अध्यक्ष और गोदरेज अप्लायंसेज के कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी कहते हैं कि भले ही इरादा सही हो लेकिन मुमकिन है कि लघु अवधि में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर कूलर, वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरीफायर आदि की कीमतों में बढ़ोतरी हो। एसी और बड़ी स्क्रीन टीवी सेट पर वस्तु एवं सेवा कर में 28 फीसदी से 18 फीसदी कटौती करने पर विनिर्माताओं को मदद मिलेगी। इसके साथ ही खरीदार भी कीमत में बढ़ोतरी को झेल पाएंगे और मांग बढ़ेगी। एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के शीर्ष अधिकारी के मुताबिक चीन में उत्पादन इकाइयां बंद रहेंगी तब प्रमुख पुर्जों की कम आपूर्ति से कीमतें बढ़ेंगी। उनका कहना है, 'टच पैनल और टीवी के फ्लैट पैनल की कीमतों में काफी तेजी दिख रही है ऐसे में इस वक्त यह जरूरी है कि आयात शुल्क में कटौती कर दी जाए।' आईडीसी के शोध निदेशक नवकेंद्र सिंह ने बताया, 'स्थानीय निर्माण के लिए जोर देने के लिए सरकार ने आयातित वस्तुओं पर ज्यादा शुल्क लगाने का जो कदम उठाया है वह पूरी तरह सही नहीं है।'